वर्ष: 6 अंक: 17

1-15 मार्च, 2026 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

राष्ट्र की 'प्रगति' योजनाओं में गति

विकसित भारत @ 2047, एक राष्ट्रीय संकल्प, एक समयबद्ध लक्ष्य है और राष्ट्रीय हित में इस लक्ष्य की प्राप्ति में 'प्रगति' मंच बना एक मजबूत आधारस्तंभ...

ई-कॉपी के लिए QR स्कैन करें

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल : 10 मार्च स्थापना दिवस

कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण

बीते 57 वर्षों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने राष्ट्रीय सुरक्षा में स्वर्णिम मानक सुनिश्चित किए हैं। 'सुरक्षा कवच' कहे जाने वाले सीआईएसएफ के जवान देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों सहित पोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो सहित कई स्थानों में दैनिक एक करोड़ से अधिक लोगों की आवाजाही को हर खतरे से रखते हैं सुरक्षित...

- देश के औद्योगिक, शैक्षणिक विकास और सुचारू संचालन में सीआईएसएफ जवानों का योगदान महत्त्वपूर्ण।
- देश के नए संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ जवान संभाल रहे।
- विनय और संयम के साथ बिना किसी चूक के सीआईएसएफ जवान दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन 70 लाख से ज्यादा यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते हैं।

250 पोर्ट की सुरक्षा जिम्मेदारी भी संभालते हैं।

"केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बल अपनी व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए जाना जाता है। यह बल आवश्यक बुनियादी ढांचे की रक्षा करते हुए और हर दिन अनगिनत लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करके हमारी सुरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण वास्तव में सराहनीय है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 6, अंकः 17 I 1-15 मार्च, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

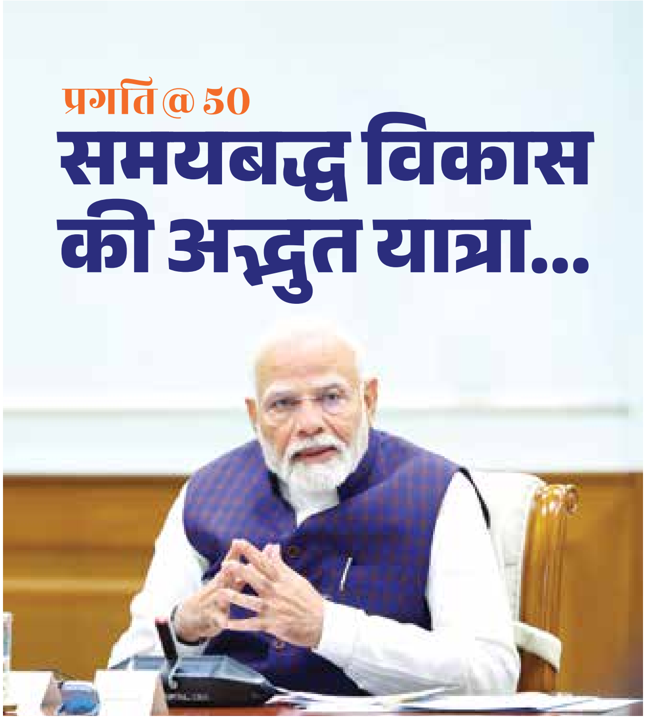

प्रगति @ 50
समयबद्ध विकास की अद्भुत यात्रा...

आवरण कथा

मार्च 2015 में बने 'प्रगति' मंच ने बीते एक दशक की यात्रा में 50 बैठकें कर 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 382 परियोजनाओं को गति दी है। इस अनोखी पहल से देश के विभिन्न राज्यों में करोड़ों रुपये की अटकी-भटकी और लटकी परियोजनाएं एक के बाद एक तेजी से पूरी हो रही हैं। इससे सुनिश्चित हो रहा है 140 करोड़ नगरिकों का विकास... | 12-31

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन केवल भवन नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति में आए परिवर्तन के प्रतीक हैं। जहां भाव राज का नहीं, सेवा का है। | 7-9

राष्ट्र गीत के सभी छह अंतरे गाएं...

समय-3 मिनट 10 सेकेंड

राष्ट्र गीत वन्दे मातरम् के प्रति सम्मान को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए नए निर्देश | 10-11

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व : राइफलमैन संजय कुमार
दुश्मन के हथियार से ही किया उनका सफाया | 6

कनेक्टिविटी को गति और शहरी चुनौती कोष शुरू करने को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय | 32-34

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र : पढ़ाई और कला दोनों उपयोगी
'परीक्षा पे चर्चा 2026' एपिसोड-2 में पीएम मोदी ने बच्चों से की बातचीत | 35-37

अब आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा भारत
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम मोदी का जवाब | 38-41

ईटी नाउ समिट 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन
...इसलिए पूरी व्यवस्था बदलने पर किया काम | 42-43

सुरक्षा और विकास का नया अध्याय
पीएम मोदी ने असम दौरे पर दी विकास की सौगातें | 44-45

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट-एक्सपो 2026
नए विचार, नवाचार और इरादों का सशक्त संगम | 46-47

...ताकि विकास की प्रेरक शक्ति बन नेतृत्व करे आधी आबादी
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष | 48-51

मैत्री से रणनीतिक साझेदारी तक
पीएम मोदी की दो दिवसीय मलेशिया यात्रा पर हुए महत्वपूर्ण समझौते | 52-53

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से खुले नए अवसर
विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व आर्थिक शक्तियों के बीच हुआ समझौता | 54-56

प्रकाशकः कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

‘प्रगति’

विकास की गति का परिवर्तनकारी मंच

सादर नमस्कार।

जन शक्ति किसी भी सरकार की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ऐसे में नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई कल्याणकारी परियोजनाएं अगर समय पर साकार नहीं हो तो उसका सीधा असर राष्ट्र की प्रगति पर पड़ता है। एक समय था जब परियोजनाएं शुरू तो होती थी लेकिन पूरी नहीं हो पाती थी। संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्वय के अभाव में न तो समस्याओं का समाधान हो पाता था और न ही उचित मॉनिटरिंग। इस कारण विकास की गति ठहर जाती थी, परियोजनाओं की लागत बढ़ती रहती थी। ऐसे में वर्तमान केंद्र सरकार ने मार्च 2015 में तकनीक पर आधारित एक ऐसे बहुआयामी मंच-प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की पहल की जो बीते एक दशक की यात्रा में गेमचेंजर बन गई है। प्रगति मंच पर आने वाली सभी परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसमें संबंधित विभाग, मंत्रालय, राज्य के अधिकारीऔर सभी हितधारक शामिल होते हैं। यहां समस्याओं का उचित समाधान करते हुए परियोजनाओं को गति दी जाती है।

पिछले दस वर्षों में इस मंच ने निरंतर समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन और स्पष्ट दिशा से देश के विकास को गति दी है। हाल ही में प्रगति की 50वीं बैठक संपन्न हुई। अभी तक इस मंच ने 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 382 राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं को नया स्पीड और स्केल दिया है। प्रगति मंच आज समय पर पूरे होने वाले कार्यों का पर्याय बन गया है। ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल ने भी अपने अध्ययन में इस पहल को परिवर्तनकारी बताया है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में ‘प्रगति’ की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। यही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर चक्र से सम्मानित राइफल मैन संजय कुमार, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता पर विशेष सामग्री, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का संपादित अंश, उनकी मलेशिया यात्रा, परीक्षा पर चर्चा सहित पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस और बैक कवर पर 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

पत्रिका में शामिल सामग्री काफी प्रेरक, पढ़ कर खुशी हुई

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ कर बहुत खुशी हुई। इस पत्रिका में शामिल जानकारी अच्छी है। साथ ही भारत के लोगों को और करीब लाने के लिए आपका धन्यवाद। इसमें शामिल सामग्री भी काफी प्रेरक लगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की खबरें उपयोगी है। यह पत्रिका बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन की गई है।

श्रीकृष्ण मंडल

देश के विकास के लिए की जा रही पहलों की सही जानकारी

विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली पत्रिका प्रकाशित करने लिए न्यू इंडिया समाचार की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि नागरिकों को अच्छी तरह से जानकारी देने की आपकी कोशिशों में आपको लगातार सफलता मिले। इस पत्रिका को पढ़ने से युवाओं को सरकारी पॉलिसी और देश के विकास के लिए की जा रही पहलों की साफ और सही समझ मिलती है।

thirubjp2020@gmail.com

भारत सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत और भरोसेमंद जानकारी

न्यू इंडिया समाचार एक बेहतरीन पत्रिका है जो भारत सरकार की अलग-अलग पहलों और स्कीमों के बारे में विस्तृत और भरोसेमंद जानकारी देती है। मुझे इसका कंटेंट बहुत जानकारी देने वाला और काम का लगा। भारत खुशकिस्मत रहा है कि उसे इतना मजबूत और जिम्मेदार प्रधानमंत्री मिला है जो सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है। न्यू इंडिया समाचार इन बातों को नागरिकों के सामने स्पष्ट रूप से पेश करने में अहम भूमिका निभाता है, जो सच में तारीफ के काबिल है।

चौहान मोहित

mohit.cm1326@gmail.com

लेख और रिपोर्ट बहुत ही प्रेरक

अभी न्यू इंडिया समाचार का अंक पढ़ रहा था। इसमें जो लेख और रिपोर्ट पढ़ी वह बहुत प्रेरक लगी। साथ ही, यह ही कहना है कि न्यू इंडिया समाचार हर बार बहुत जानकारी परक और दिलचस्प लगती है।

एच. शर्मा

hsonai@hotmailcom

परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार

मैं सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। मैं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का नियमित पाठक हूं। यह पत्रिका मेरी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित हो रही है। यह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस पत्रिका के माध्यम से अभ्यर्थियों को भारत के विकास और प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी मदद मिलती है। इसमें प्रकाशित आलेख सरल भाषा में होते हैं।

मोहित मौर्य

studentindia72@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003.
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर शनिवार-रविवार को दोपहर 3:10 से 3:25 बजे तक सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली में मिल सकेगा कैशलेस इलाज

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के अंतर्गत आने वाली सभी 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मेडिक्लेम के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। संस्थान ने फरवरी के पहले पखवाड़े में इसके लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक समझौता किया है।

एआईआईए के निदेशक प्रो. (वैद्य) पी. के. प्रजापति ने कहा कि इस पहल से आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक अधिक आसानी से और कम खर्च में पहुंचेंगी। इससे मरीजों का भरोसा बढ़ेगा और उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा। आयुष मंत्रालय ने पहली बार, लाभार्थियों को इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब देने और आयुष इंश्योरेंस कवरेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष हेल्थ इंश्योरेंस हेल्पलाइन 1800-11-0008 शुरू की है।

साइबर अपराधियों से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाए

देश में डिजिटल सेवाएं बढ़ने के साथ-साथ ऑनलाइन ठगी के भी नए-नए तरीके निकाले जा रहे हैं। यही वजह है कि बढ़ती साइबर ठगी से नागरिकों को बचाने के लिए सरकार ने कई स्तर पर प्रयास किए हैं। इसी दिशा में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की शुरूआत की गई है। आई4सी के तहत सभी तरह के साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (**https://cybercrime.gov.in**) के साथ ही नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) की शुरुआत 2021 में की गई थी। इसके अनुसार 31 दिसंबर, 2025 तक देश में 23.61 लाख से अधिक शिकायतों में 8,189 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' भी चलाई जा रही है।

भारत करेगा 6-जी में विश्व का नेतृत्व

भारत अब प्रौद्योगिकी के मामले में अनुसरणकर्ता नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत की संचार क्रांति अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांवों तक पहुंच रही है जिससे नागरिकों के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के स्तरों में बदलाव आया है। संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने संसद में कहा कि भारत ने 4-जी में दुनिया का अनुसरण किया, 5-जी में दुनिया के साथ कदम मिलाया और 6-जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

भारत ने विश्व में सबसे तेज गति से 5-जी सेवा शुरू की है। मात्र 22 महीनों में देश के 99.9 प्रतिशत जिलों में 5-जी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। देश में अभी 40 करोड़ नागरिक 5जी से लाभांवित हैं, वर्ष 2030 तक 1 अरब नागरिकों को 5-जी कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी।

भारत की क्रिकेट प्रतिभाओं की चमक

भारत का खेल इकोसिस्टम बीते दशक में काफी मजबूत हुआ है। चाहे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 हो, दृष्टिबाधित महिला टी-20 विश्व कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो या एशिया कप 2025 का जीतना, हमारे खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर लोहा मनवा रहे हैं। नया गौरव अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दिया है जिसने रिकॉर्ड छठी बार एक दिवसीय विश्व कप जीता है। यह जीत जिम्बाब्वे के हरारे में हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी और कहा, "विश्व कप घर लाने के लिए हमारी U-19 टीम पर गर्व है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है और असाधारण कौशल दिखाया है। यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। खिलाड़ियों को आने वाले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।" उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भी युवा चैंपियन को बधाई दी।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ बढ़ते कदम...

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पांच मॉड्यूल से युक्त समग्र संरचना तैयार कर ली है। समीक्षा के बाद इसके पहले मॉड्यूल को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस-01) के पहले मॉड्यूल के विकास और प्रक्षेपण की तैयारी जारी है। इसरो के विभिन्न केंद्रों में बीएएस-01 की संपूर्ण प्रणाली अभियांत्रिकी तथा उसकी अलग-अलग उप-प्रणालियों के तकनीकी विकास का कार्य प्रगति पर है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उन्नत जीवन-रक्षक प्रणालियों और आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। यह निम्न पृथ्वी कक्षा में लंबे समय तक मानव के रहने को संभव बनाएगा। इसके माध्यम से उन्नत वैज्ञानिक शोध और नई तकनीकों का परीक्षण किया जा सकेगा, जिनका समाज और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह निम्न पृथ्वी कक्षा से आगे के भारतीय मानव अंतरिक्ष अभियानों को भी सहयोग देगा। सरकार ने पहले के मिशनों, बीएएस-1 के विकास और प्रक्षेपण को गगनयान कार्यक्रम के संशोधित दायरे में शामिल करते हुए इसका बजट 20,193 करोड़ रुपये कर दिया है।

260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनेंगे चरणबद्ध तरीके से सेवा में आएंगे

भारतीय रेलवे लगातार आधुनिक हो रही है। सालाना 720 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही को संभालती है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन के रूप में सेवाएं लगातार जोड़ी जा रही हैं। इसी कड़ी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हाल ही में की गई है। सरकार इसके विस्तार की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट तैयार कर रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निर्माण कार्यक्रम को बीईएमएल और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और तकनीकी साझेदारों द्वारा प्रोटोटाइप विकास, परीक्षण और श्रृंखला उत्पादन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। कुल 260 रैक निर्माण की योजना है जिसे मांग और परिचालन तत्परता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सेवा में उतारा जाएगा।

दुश्मन के हथियार से ही किया उनका सफाया

जन्म : 3 मार्च 1976

असाधारण वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन संजय कुमार ने कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को उसी के हथियार से धूल चटाई। लहूलुहान होने के बावजूद इस वीर जवान ने रणभूमि से वापस आने से इनकार कर दिया। तब तक दुश्मनों से जूझते रहे, जब तक प्वाइंट फ्लैट टॉप दुश्मनों से पूरी तरह से खाली नहीं करा लिया...

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कलोल बकैण गांव में 3 मार्च 1976 को जन्मे संजय कुमार तीन बहनों और दो भाई में सबसे छोटे थे। वह बचपन से ही सेना में जाने का सपना संजोये हुए थे। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शामिल रहे अपने चाचा और सेना में भर्ती अन्य गांव वालों के द्वारा सुनाई गई युद्ध की वीरतापूर्ण गाथाओं ने उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दृढ़ निश्चयी संजय कुमार आखिरकार 1996 में सफल हुए और जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए।

4 जुलाई 1999 को 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स की एक कंपनी के लीडिंग स्काउट में शामिल राइफलमैन संजय कुमार को जम्मू-कश्मीर के मुश्कोह घाटी को दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए भेजा गया। चोटी पर पहुंचने के बाद, वह दुश्मन सेना के एक बंकर से की जा रही जबरदस्त गोलीबारी की चपेट में आ गए। आमने-सामने की लड़ाई में उन्होंने तीन घुसपैठियों को मार गिराया और स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार्यवाही से दुश्मन के सैनिक बिल्कुल अचंभित रह गए और एक यूनिवर्सल मशीन गन छोड़ कर भागने लगे। राइफलमैन संजय कुमार ने वह यूनिवर्सल मशीन गन उठाई और भागते हुए सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई और दुश्मन सैनिक मारे गए। बहुत ज्यादा खून बहने के बावजूद, उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्यवाही से उनके साथियों को प्रेरणा मिली और उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल कर अंततः फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

उच्च कोटि की वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए राइफलमैन संजय कुमार को लड़ाई के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायब सुबेदार संजय कुमार को 2 जुलाई 2014 को भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड ऑफिसर बनाया गया। इतना ही नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षक संजय कुमार को सेना के प्रति समर्पण और निष्ठा के लिए फरवरी 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। वहीं वर्ष 2026 में भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस पर उन्हें मानद कैप्टन पद से नवाजा।

सेवा और कर्तव्य का ‘नव तीर्थ’

नई प्रशासनिक संस्कृति और सुशासन की दिशा में भारत सरकार द्वारा विकसित सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन केवल भवन नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति में आए परिवर्तन के प्रतीक हैं। यह परिवर्तन केवल संरचना का नहीं बल्कि सोच और कार्यशैली में आए बदलाव का भी है। जहां भाव राज का नहीं, सेवा का है। विजया एकादशी के पावन अवसर पर 13 फरवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता बना-सेवा तीर्थ। इसी अवसर पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रूप में कर्तव्य भवन-1 व 2 का भी हुआ उद्घाटन, जो बन गया है विकसित भारत के संकल्प की यात्रा के नए आरंभ का साक्षी...

नया भारत युग प्रवर्तक पथ की ओर अग्रसर है। विक्रम संवत 2082, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, 24 माघ, शक संवत 1947 जो वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 13 फरवरी 2026 है, यह तारीख भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरुआत की साक्षी बनी। दरअसल, विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। औपनिवेशिक शासन की आवश्यकताओं और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का निर्माण हुआ था। उस समय तत्कालीन वायसराय ने कहा था यह संरचनाएं ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बनाई गई हैं। रायसीना हिल्स का चयन इसलिए किया गया था ताकि ये इमारतें अन्य सभी से ऊपर रहें और कोई इनके बराबर खड़ा न हो सके। रायसीना हिल्स की तुलना में सेवा तीर्थ परिसर सीधे धरातल से जुड़ा हुआ है। जहां साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण औपनिवेशिक मानसिकता को लागू करने के लिए किया गया था वहीं आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इन भवनों से लिए जाने वाले निर्णय 140 करोड़ नागरिकों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने की नींव बनेंगे।

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का पहला क्वार्टर अब पूरा हो चुका है। यह आवश्यक है कि विकसित भारत का विजन न केवल नीतियों और योजनाओं में, बल्कि कार्यस्थलों और भवनों में भी प्रतिबिंबित

सेवा तीर्थ : यहां अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं। पहले ये सभी अलग-अलग स्थानों से संचालित होते थे।

कर्तव्य भवन-1 और 2 : इनमें वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉर्पोरेट कार्य, शिक्षा, संस्कृति, विधि एवं न्याय, सूचना एंव प्रसारण, कृषि एवं कृषि कल्याण, रसायन एवं उर्वरक और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल हैं।

इन भवनों में हैं आधुनिक सुविधाएं

दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, व्यवस्थित पब्लिक इंटरफेस जोन और सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शन सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन परिसरों में रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जल संरक्षण के उपाय और कचरा प्रबंधन समाधान की व्यवस्था है। इन भवन परिसरों में एक व्यापक सुरक्षा ढांचा भी शामिल है, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और एडवांस्ड इमरजेंसी रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर।

> *सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन...भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे, वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

कर्तव्य की बुनियाद पर होगा विकसित भारत का निर्माण

कोटि-कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है- कर्तव्य!
कर्तव्य आरंभ है, कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है।
करुणा और कर्मठता के स्नेह-सूत्र में बंधा कर्म है- कर्तव्य!
संकल्पों की आस है- कर्तव्य!
परिश्रम की पराकाष्ठा है- कर्तव्य!
हर समस्या का समाधान है- कर्तव्य, विकसित भारत का विश्वास है- कर्तव्य !
कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है।
सबका साथ-सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है- कर्तव्य !
राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है- कर्तव्य !
हर जीवन में ज्योति जगा दे, वो इच्छाशक्ति है- कर्तव्य !
आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है- कर्तव्य !
भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है- कर्तव्य !
मां भारती की प्राण-ऊर्जा का ध्वजवाहक है- कर्तव्य !
राष्ट्र के प्रति भक्ति-भाव से किया हर कार्य है- कर्तव्य!
'नागरिक देवो भव:' की साधना का जागृत पथ है- कर्तव्य !

हों। जिन स्थानों से देश का शासन चलाया जाता है वे प्रभावी, प्रेरणादायक और प्रेरक होने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में जगह की कमी थी और सुविधाएं सीमित थीं, लगभग सौ साल पुराने होने के कारण भवन भीतर से जर्जर हो रहे थे। स्वतंत्रता के दशकों बाद भी, भारत सरकार के कई मंत्रालय दिल्ली में 50 से अधिक अलग-अलग स्थानों से कार्य कर रहे थे। हर साल इन मंत्रालयों के भवनों के किराए पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि कार्यालयों के बीच आवाजाही करने वाले 8,000 से 10,000 कर्मचारियों के लिए दैनिक लॉजिस्टिक लागत भी वहन करनी पड़ती थी। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के निर्माण से इन खर्चों में कमी आएगी और कर्मचारियों के समय की बचत होगी।

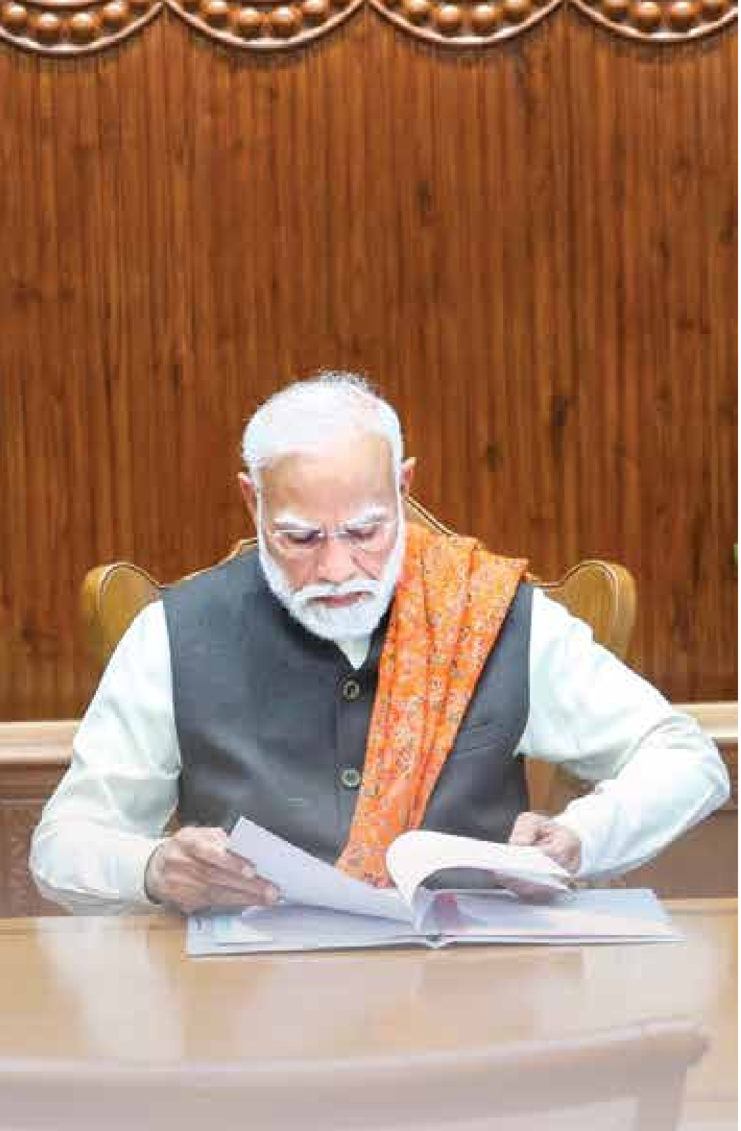

नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है- सेवा तीर्थ।

सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है, सेवा की भावना ही भारत की पहचान है।
शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है।
सेवा तीर्थ, ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है।
सेवा तीर्थ यानी- नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल!
सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल!
आज भारत के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है।
हमें करोड़ों देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलानी है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है और ये काम सेवा के सामर्थ्य से ही सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पीएम मोदी ने पुराने भवन को राष्ट्र के लिए एक संग्रहालय के रूप में समर्पित करने के निर्णय की घोषणा की, जिससे इसे युगे युगीन भारत संग्रहालय का हिस्सा बनाया जाएगा। यह भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। वर्ष 2014 में देश ने यह संकल्प लिया कि अब औपनिवेशिक मानसिकता नहीं चलेगी। इस सोच को बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शहीदों के सम्मान में राष्ट्रीय समर स्मारक और पुलिस के शौर्य को मान्यता देने के लिए पुलिस स्मारक का निर्माण हुआ। रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया।

पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि सेवा तीर्थ केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संकल्प है-नागरिकों की सेवा के माध्यम से एक पवित्र स्थान और सेवा के प्रण को सिद्धि तक ले जाने का एक केंद्र। तीर्थ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि तीर्थ वह है जिसमें तारने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता हो। पिछले ग्यारह वर्षों में गवर्नेंस का एक नया मॉडल उभर कर सामने आया है, जहां निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में नागरिक हैं। "नागरिक देवो भवः" केवल एक वाक्यांश नहीं है, बल्कि यह हमारी कार्य-संस्कृति है, जिसे इन नए भवनों में प्रवेश करते समय सभी अधिकारियों को आत्मसात करना चाहिए।

करोड़ों नागरिकों के जीवन को बनाएगा आसान

सेवा तीर्थ में लिया जाने वाला हर निर्णय, आगे बढ़ने वाली हर फाइल और यहां बिताया गया हर पल 140 करोड़ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। पीएम मोदी ने प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी और कर्मयोगी से आग्रह किया कि जब भी वे इस भवन में कदम रखें, तो एक पल के लिए रुकें और स्वयं से पूछें-क्या आज का उनका कार्य करोड़ों नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यही आत्म-चिंतन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा।

नए भवन तय करेंगे विकसित भारत-2047 की दिशा

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में लिया गया हर निर्णय केवल एक फाइल की मंजूरी नहीं होगा, बल्कि वह विकसित भारत 2047 की दिशा निर्धारित करेगा। हर संस्थान, हर अधिकारी, हर कर्मचारी और हर कर्मयोगी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विजन साझा करते हुए कहा कि सेवा तीर्थ को सेंसिटिव गवर्नेंस का सिंबल और नागरिक केंद्रित प्रशासन का रोल मॉडल बनना चाहिए। ■

आधिकारिक वंदे मातरम् और विस्तृत प्रोटोकॉल

राष्ट्रगीत के सभी छह अंतरे गाएं... अवधि-3 मिनट 10 सेकेंड

देश राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी उत्सव की कड़ी में केंद्र सरकार ने अब राष्ट्र गीत के प्रति सम्मान और उचित शिष्टाचार का पालन करने को लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें शामिल है सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए निर्देश। जब भी राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान दोनों गाए या बजाए जाएं तो राष्ट्र गीत पहले गाएं। राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे प्रमुख राजकीय अवसरों पर आधिकारिक राष्ट्र गीत अनिवार्य...

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर आधिकारिक प्रोटोकॉल स्थापित करने वाले भारत सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश में बताया गया है कि सरकारी समारोहों में इसे कैसे और कब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नागरिकों से अपेक्षित आचरण, राष्ट्र गीत गाने या बजाने के तरीके के साथ उसकी समयावधि की भी जानकारी दी गई गई।

अवधि : राष्ट्र गीत को गाने अथवा बजाने का समय लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।

राष्ट्र गीत पहले : एक जरूरी बात यह है कि अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान दोनों गाए या बजाए जाएं तो राष्ट्र गीत पहले गाया या बजाया जाएगा, उसके बाद 'राष्ट्रगान'।

सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशिष्ट छूट जब कभी राष्ट्र गीत का गायन या वादन हो तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। लेकिन समाचार या किसी वृत चित्र के दौरान राष्ट्र गीत फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं हैं। दर्शकों के खड़े होने से राष्ट्र गीत के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पड़ेगी। अशांति या गड़बड़ी उत्पन्न होती है।

दिशानिर्देशों में की गई है यह अनुशंसा : जब वंदे मातरम् का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाता है तो उससे पहले ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से गायन की शुरुआत का संकेत दिया जाना चाहिए।

राष्ट्र गीत के गायन की (गीत को बजाने से भिन्न) अनुमति जिन अवसरों पर राष्ट्र गीत के गायन की (गीत को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण सूची देना संभव नहीं है। लेकिन राष्ट्र गीत को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ-साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए। गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए।

राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' के बोल इस प्रकार हैं...

वंदे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वंदे मातरम्।

शुभज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वंदे मातरम्।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले मां तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वंदे मातरम्।

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मां शक्ति,
हृदये तुमि मां भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गडि मंदिरे-मंदिरे।
वंदे मातरम्।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वंदे मातरम्।

विद्यालयों में सहगान : सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्र गीत के सहगान से प्रारंभ होना चाहिए। विद्यालयों के प्रबंधन को छात्रों में राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

राष्ट्र गीत का वादन

राष्ट्र गीत का आधिकारिक संस्करण, निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जाएगा

- सिविल सम्मान समारोहों के अवसर पर।
- औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय।
- आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में।
- राज्यपाल / उपराज्यपाल के अपने राज्य संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय।
- जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए।
- किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्र गीत बजाया जाएगा जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों।

प्रगति @ 50

समयबद्ध विकास की अद्भुत यात्रा...

भारत जब 2014 में विकास की नई दिशा में बढ़ रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महसूस किया कि बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं की सफलता केवल मंजूरी देने से नहीं, बल्कि समय पर, परस्पर समन्वय और जवाबदेह क्रियान्वयन से सुनिश्चित होती है। इसी सोच से मार्च 2015 में बने 'प्रगति' मंच ने बीते एक दशक की यात्रा में 50 बैठकें कर 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 382 परियोजनाओं को गति दी है। इस अनोखी पहल से देश के विभिन्न राज्यों में करोड़ों रुपये की अटकी-भटकी और लटकी परियोजनाएं एक के बाद एक तेजी से पूरी हो रही हैं। इससे सुनिश्चित हो रहा है 140 करोड़ नगरिकों का विकास...

- उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना को स्वीकृति मिली 1978 में और चार दशक की देरी के बाद वर्ष 2021 में पूरी हुई।
- केरल में कोल्लम बाईपास परियोजना को स्वीकृति मिली 1972 में और पांच दशक की देरी के बाद वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया।
- बिहार में कोसी रेल महासेतु को स्वीकृति मिली 2003-04 में और दो दशक की देरी के बाद वर्ष 2020 में पूरी हुई।
- असम में बोगीबील सेतु परियोजना को स्वीकृति मिली 1997 में और 2 दशक की देरी के बाद वर्ष 2018 में पूरी हुई।
- अटल टनल परियोजना को मंजूरी मिली वर्ष 2000 में और दो दशक की देरी के बाद वर्ष 2020 में पूरी हुई।
- ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरीफेरल परियोजना को स्वीकृति मिली 2006 में और एक दशक की देरी के बाद 2016 और 2018 में पूरी हुई।
- नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को स्वीकृति मिली 2007 में और करीब दो दशक की देरी से दिसंबर 2025 में पूरी हुई।
- जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना को स्वीकृति मिली 1994 में और लगभग तीन दशक की देरी के बाद जून 2025 में पूरी हुई।

अब जरा सोचिए, क्या किसी परियोजना में इतनी लंबी देरी कभी राष्ट्रहित में हो सकती है? आखिर पहले की कार्यशैली ऐसी क्यों थी कि काम एक बार अटक जाए तो वर्षों तक वहीं ठहरा रहता था-न जवाबदेही थी, न कोई पूछने वाला। फाइलों में योजनाएं बनती रहीं, राजनीतिक हितों के लिए घोषणाएं होती रहीं, दीप प्रज्ज्वलन और शिलान्यास भी होते रहे, लेकिन नतीजा यही रहा कि कई परियोजनाएं दशकों तक कागजों में ही लटकी रहती थीं।

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में एक टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म बनाया- 'प्रगति' यानी प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसकी हाल ही में संपन्न 50वीं बैठक विकास की यात्रा में मील का पत्थर बनी है। अभी तक

'प्रगति': एक नजर

- 'प्रगति' विकास की नई राह: एक समय था, जब विकास परियोजनाएं घोषणाओं के बाद क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत पर आकर अटक जाती थीं। केरल के कोल्लम में साढ़े तेरह किमी का बाईपास बनने में 5 दशक से ज्यादा का वक्त लगा हो या ओडिशा में खुर्दा-बलांगीर की रेल लाइन बनने में 25 साल से ज्यादा का समय।
- 'प्रगति' सूचना, संचार और तकनीक (आईसीटी) पर आधारित मल्टी मॉडल मंच है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं की समीक्षा और उसमें होने वाली बाधाओं को दूर करना है।
- 'प्रगति' की बैठकों के 50वें संस्करण तक (31 दिसंबर 2025), 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली 382 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।

सर्दियों में बर्फबारी की वजह से रोहतांग दर्रे के निकट मनाली-लेह हाईवे पांच-छह महीनों के लिए ठप पड़ जाता था और यह क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह कटा रहता था। लेकिन अब यह सड़क पूरे साल के लिए खुल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल राष्ट्र को समर्पित किया।

> *उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी, भटकी, लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

'प्रगति' प्लेटफॉर्म पर 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 382 परियोजनाओं को गति दी गई है। बैठकों में परियोजनाओं की समीक्षा होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि किस मंत्रालय या किस राज्य को क्या परेशानी हो रही है। किस कानून के कारण परेशानी हो रही है। सभी पहलुओं को बारीकी से देखने के बाद उसका समाधान निकाला जाता है। इस 'प्रगति' के क्रियान्वयन के कारण रेल, रोड, सिंचाई या ग्रामीण व्यवस्था का काम, सारी चीजों को वहां लाकर समाधान किया गया। हाल ही में जम्मू उधमपुर-श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और बर्फबारी के दिनों का एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादरों के बीच से वंदे भारत ट्रेन निकल रही है और लोग कहते हैं, गलती मत करना, यह विदेश नहीं, यह हिंदुस्तान है। लेकिन हकीकत भी जानना होगा कि यह परियोजना तीन दशक से लटकी हुई थी। जिसे वर्तमान केंद्र सरकार ने साकार करके दिखाया। इसी तरह असम का बोगीबील ब्रिज, यह बोगीबील ब्रिज अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है। कितने ही सालों तक यह प्रोजेक्ट लटका रहा, इसकी 'प्रगति' के माध्यम से समीक्षा हुई और असम सहित पूरे पूर्वोत्तर को बहुत बड़ी सुविधा वाला यह काम पूरा हो चुका है।

दरअसल, किसी भी योजना की कार्यरूप में परिणति यानी क्रियान्वयन क्या होता है, आज देश के समक्ष इसके हजारों उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन सवाल है कि दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही क्यों उठाई? सही अर्थों में यही नीति, नीयत और निर्णय की त्रिवेणी है जो किसी

भी योजना का आधार होता है और आज 'प्रगति' इसका पर्याय बन गया है। यह केवल पुरानी परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिन परियोजनाओं की शुरुआत की, उन पर 'प्रगति' की निरंतर निगाह बनी रहती है।

'स्वागत' से 'प्रगति' विकास की नई यात्रा

'प्रगति' प्लेटफॉर्म का उदाहरण देखिए। हिमाचल में एक ट्रेन दशकों पहले ऊना के लिए संसद में घोषित हुई थी। लेकिन पीएम मोदी के शासन में आने तक कागज पर उसका चित्र तक नहीं बना था। यह विषय जब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले 'प्रगति' मंच पर आया तो समाधान हुआ और आज वह ट्रेन पहाड़ के सपनों को साकार कर रही है। ऐसे कई विषय 'प्रगति' मंच पर आए जिसमें यह देखा गया कि परियोजनाएं क्यों अटकी हैं, लागत पर क्या अंतर आया है, किस विभाग के कारण देरी हो रही है, किसने गलत तरीके से इसमें देरी की है। जो योजना 900 करोड़ रुपये में होनी थी, वह 90 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इसी तरह वर्ष 2015 में 'प्रगति' की बैठक में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विषय आया था, तो प्रधानमंत्री मोदी हैरान रह गए थे। वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में दूसरे एयरपोर्ट को लेकर नवंबर 1997 में पहली बार कमेटी बनी थी। तब से लेकर करीब-करीब 20 साल तक सिर्फ फाइलें ही इधर से उधर दौड़ती रहीं। इस बीच कितनी सरकारें आईं, कितनी चली गईं लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट की फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। 'प्रगति' की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सारे अफसरों और सारे विभागों को एक साथ आमने-सामने लाकर इस प्रोजेक्ट के बीच आ रहे सारे रोड़े दूर किए और अब

'प्रगति' की गति
और महत्व को ऐसे समझें

'प्रगति' मंच की शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई।

50 बैठकें अभी तक प्रगति की हो चुकी हैं।

382 प्रमुख राष्ट्रीय परियोजना की समीक्षा हुई।

85 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट को दी गई गति।

61 कल्याणकारी योजनाएं जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि और स्वच्छ भारत मिशन।

36 प्रमुख सेक्टर की शिकायतों का निपटारा जिसमें कोरोना, रेरा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मातृ वंदना और जन धन योजना शामिल।

7,735 मुद्दों को यहां उठाया गया जिसमें → **7,156** का समाधान कर लिया।

पूंजीगत व्यय

वित्त वर्ष-2014-15 में 4.26 लाख करोड़ रु. से वित्त वर्ष-2025-26 में साढ़े तीन गुना से ज्यादा बढ़कर अनुमानित 15.53 लाख करोड़ रु. तक पहुंचा।

समस्या निवारण तंत्र

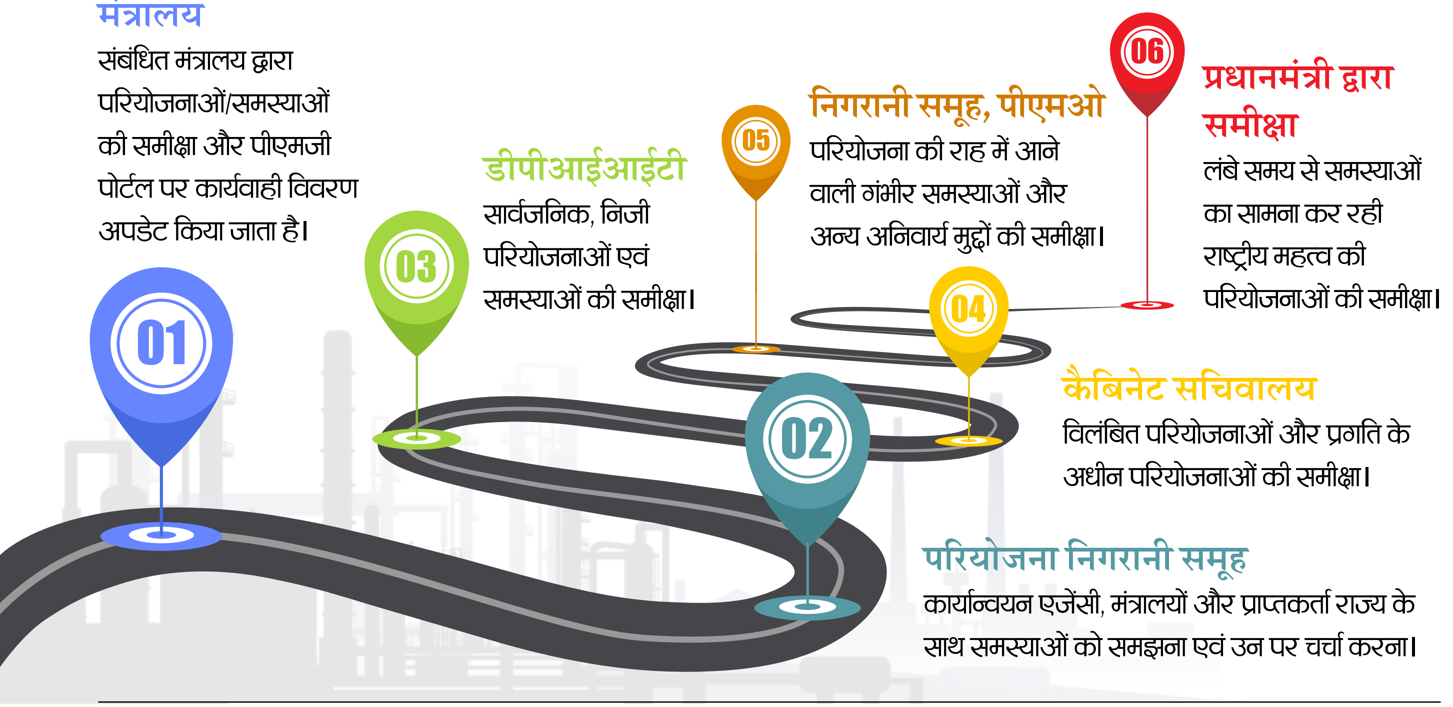

नवी मुंबई एयरपोर्ट का सपना भी साकार हो चुका है। इसी तरह 2017 में साकार हुआ दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का सपना। जिसे बनाने का फैसला 1992 में हुआ था लेकिन 23 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2014 में पीएम मोदी के शासन काल में ही इसका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ।

यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी है, ऐसी 382 परियोजनाएं आज या तो साकार हो चुकी है या कुछ होने वाली है। यह कार्य-संस्कृति में आए बदलाव का जीता जागता उदाहरण है। ऐसी परियोजनाओं की सूची बेहद लंबी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की अनोखी पहल से देश के विभिन्न राज्यों में हजारों करोड़ रुपये की अटकी-भटकी और लटकी परियोजनाएं एक के बाद के तेजी से पूरी हो रही है। परियोजनाओं को फाइलों से निकाल कर जमीन पर तय समय में उतारा जा चुका है। यह क्रांतिकारी बदलाव संभव हुआ है, 'प्रगति' प्लेटफॉर्म की मदद से। इससे न केवल भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, बल्कि लागत और समय में कमी आई है। इस चहुंमुखी विकास का लाभ दूरदराज तक किसानों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं तक सीधे पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दिशा-निर्देश से भारत सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों में सामंजस्य स्थापित हुआ है और अनेक लंबित परियोजनाएं पूर्ण हो सकी। इस प्लेटफॉर्म पर विकास परियोजनाओं की निगरानी प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करते हैं। यह 25 मार्च 2015 से हर महीने इसी तरह बैठक कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से पहचान की गई लगभग 96% समस्याओं को हल किया गया, जिससे देरी, लागत वृद्धि और परस्पर समन्वय की खामियों में भारी कमी आई। इस मंच पर हर विभाग से साथ न केवल चर्चा होती है बल्कि मौके पर ही तत्काल समाधान निकाला जाता है। इस प्लेटफॉर्म की नींव में प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात का अनुभव है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते पीएम मोदी ने स्वागत प्लेटफॉर्म शुरू किया था। एक ऐसा तकनीकी साधन, जिससे जनता की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती और उनका समयबद्ध निराकरण होता था। स्वागत (SWAGAT) ने पारदर्शिता और जवाबदेही की नींव रखी। इसी अनुभव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया और 'प्रगति' के रूप में एक एकीकृत, बहु-एजेंसी मंच तैयार किया जो संघवाद का उम्दा उदाहरण बना। इसके बाद बड़ी और प्रमुख परियोजनाओं से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के साथ उसमें देरी न हो इसके लिए सबको एक ही छत के नीचे लेकर आया गया। यहां मंत्रालय और विभाग अलग-अलग काम करने से परे जाकर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं कि 2014 से सरकार ने कार्य-पूर्णता और जवाबदेही को संस्थागत बनाने के लिए काम किया है।

'प्रगति' इकोसिस्टम में मुद्दों का समाधान

7,735 मुद्दे उठाए गए | **7,156 मुद्दों का समाधान किया गया**

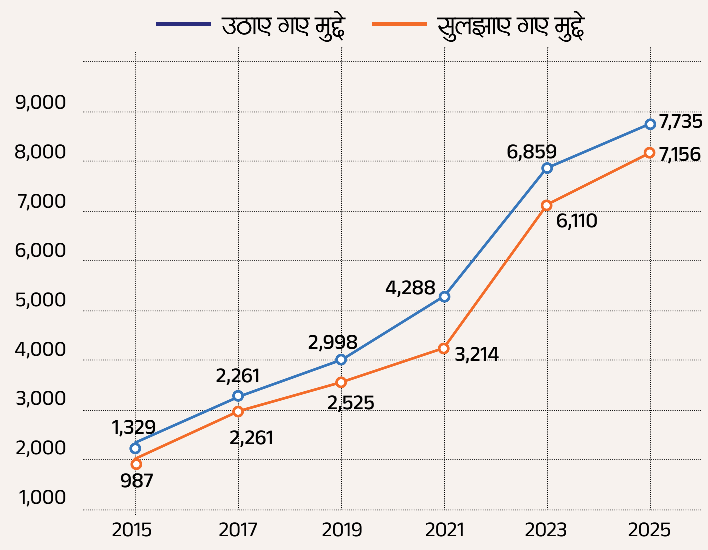

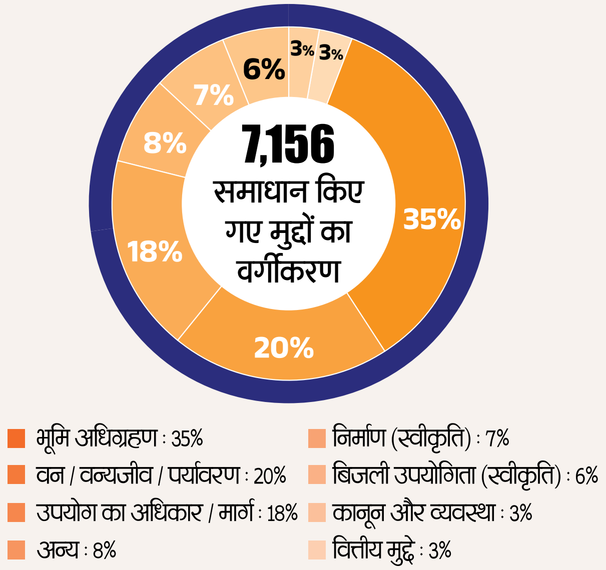

एक ऐसी प्रणाली तैयार की गई है जिसमें काम को लगातार फॉलोअप के साथ आगे बढ़ाया जाता है। इसे तय समय और तय बजट में पूरा किया जाता है। उनका कहना है कि पहले शुरू की गई परियोजनाएं जो अधूरी रह गई थीं या जिन्हें भुला दिया गया था, उन्हें राष्ट्रीय हित में पुनर्जीवित और पूरा किया गया है। कई परियोजनाएं जो दशकों तक अटकी हुई थीं, उन्हें 'प्रगति' प्लेटफॉर्म के तहत लाने के बाद पूरा किया गया।

टीम भारत का भव्य उदाहरण

प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि परियोजनाएं केवल इरादे की कमी के कारण असफल नहीं होतीं। कई परियोजनाएं समन्वय की कमी और अलग-अलग काम करने पर आधारित कार्यप्रणाली के कारण असफल होती हैं। 'प्रगति' मंच इसके समाधान के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लेकर आई, जो साझा परिणाम हासिल करने के अनुरूप है। 'प्रगति' आज सहयोगी संघवाद का एक प्रभावी मॉडल है, जहां केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 50वीं बैठक में बताया कि इसकी शुरुआत से अब तक लगभग 500 भारत सरकार के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव 'प्रगति' बैठक में भाग ले चुके हैं। 'प्रगति' मंच ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किये हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निवेश हुए हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अब 'प्रगति' के जरिए अगले चरण में मंत्र दिया-"सरल बनाने के लिए सुधार करें, कार्य-पूर्णता के लिए काम करें, प्रभाव डालने के लिए परिवर्तन करें।"

तकनीक से 'प्रगति' का नया मार्ग

"जब योजनाओं में गति आती है, तभी देश में प्रगति आती है।" साहसिक सुधारवाद के प्रणेता बन चुके पीएम मोदी की यही सोच नए विश्वास के साथ नई शुरुआत की प्रतीक बन चुकी है। कभी असंभव या छोटा मानकर नियति के भरोसे छोड़ दी गई उम्मीदें अब साकार हो रही हैं। लीक से हटकर शुरू की गई 'प्रगति' पहल नए भारत में बदलाव की पटकथा तैयार कर रही है, ताकि 2047 में देश जब अपनी आजादी की शताब्दी वर्षगांठ मनाए, तब इन्हीं संकल्पों की सिद्धि उसे दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार करा सके। नए भारत का लक्ष्य, लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझते हुए तेज गति से काम करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है-केंद्रीय स्तर पर 'प्रगति' नाम से बनाई गई व्यवस्था। देश की अलग-अलग योजनाओ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी लाने में इस 'प्रगति' प्लेटफॉर्म की

ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल की स्टडी

शीर्ष नेतृत्व से दिशा: **PRAGATI** आज जिस स्वरूप में है, वह निर्णायक और सक्रिय नेतृत्व का परिणाम है-विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। शीर्ष स्तर पर नियमित मासिक समीक्षा और सीधी भागीदारी ने न केवल स्पष्ट दिशा तय की, बल्कि समस्याओं के शीघ्र समाधान को गति दी। सभी हितधारकों में टीमवर्क की सामूहिक भावना को मजबूत किया।

PRAGATI के प्रभाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इसने सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। सड़कों, रेल, जल और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाकर **PRAGATI** ने करोड़ों भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार किया है। इस मंच ने अपनी कार्यप्रणाली में स्थिरता को भी मूल तत्व के रूप में शामिल किया है। पर्यावरणीय स्वीकृतियों को शीघ्रता प्रदान करने में सहायता और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भारत का विकास समावेशी होने के साथ-साथ सतत भी हो।

भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (**NIP-FP**) के अध्ययनों का हवाला देते हुए केस स्टडी में कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए प्रत्येक एक रुपये के बदले देश को सकल घरेलू उत्पाद (**GDP**) में लगभग 2.5 से 3.5 रुपये का लाभ मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति 'विकसित भारत 2047' पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक महत्वाकांक्षी रोडमैप, जिसका उद्देश्य भारत को उसकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक 'विकसित राष्ट्र' बनाना है। इस पहल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, तकनीकी उन्नति और सतत विकास सहित राष्ट्रीय विकास के व्यापक लक्ष्य शामिल हैं। इसके अंतर्गत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। 100 प्रतिशत साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने जैसे प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

बहुत बड़ी भूमिका है। 'प्रगति' की बैठकों में यह निर्धारित होता है कि सभी हितधारकों के साथ सीधा संवाद करके दशकों से अटकी हुई परियोजनाओं का हल निकाला जा सके। सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से राष्ट्र के विकास को गति मिलती है। आज छोटे उद्योगों को, विशेष रूप से एमएसएमई को एक आत्मविश्वास मिला है कि वह दुनिया के बड़े बाजारों से प्रतिस्पर्धा कर सके। आज उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि तकनीक से जुड़ाव और उसे सुशासन का महत्वपूर्ण जरिया बनाने की कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी आती है। जमीनी स्तर पर उनका लोगों के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत जुड़ाव तो है ही, साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। उन्हें भारत के सबसे ज्यादा 'टेक-सेवी' नेता के रूप में भी जाना जाता है। वो लोगों तक पहुंचने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तकनीक के संयोजन से उन्होंने 'प्रगति' का ऐसा फोरम बनाया जिससे लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को नई दिशा मिल रही है।

ऑक्सफोर्ड के अध्ययन ने माना- गेमचेंजर

दिसंबर 2024 में ऑक्सफोर्ड के एक अध्ययन ने भारत की प्रमुख परियोजनाओं को गति देने में 'प्रगति' की भूमिका को रेखांकित किया है। गेट्स फाउंडेशन की ओर से समर्थित ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल द्वारा एक अभूतपूर्व केस स्टडी की गई। इसका शीर्षक 'From Gridlock to Growth: How Leadership Enables India's PRAGATI Ecosystem to Power Progress' है। 'प्रगति' को भारत के डिजिटल गवर्नेंस परिदृश्य में एक गेम-चेंजर के रूप में उजागर किया है। आज 'प्रगति' प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी और शासन का एक अद्भुत संयोजन है। यह सुनिश्चित करती है कि बाधाएं दूर हों और परियोजनाएं समय पर पूरी हों।

नई परंपराओं के उदय से मिली गति

अमृत महोत्सव, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प एक नए भारत की नींव का आरंभ था। 25 साल की अमृत काल की यात्रा की शुरुआत हो या लाल किले से स्वच्छता और सैनिटरी पैड का जिक्र करके जागरूकता

प्रधानमंत्री ने 'प्रगति' प्लेटफॉर्म पर इन सेक्टर की परियोजनाओं की समीक्षा की

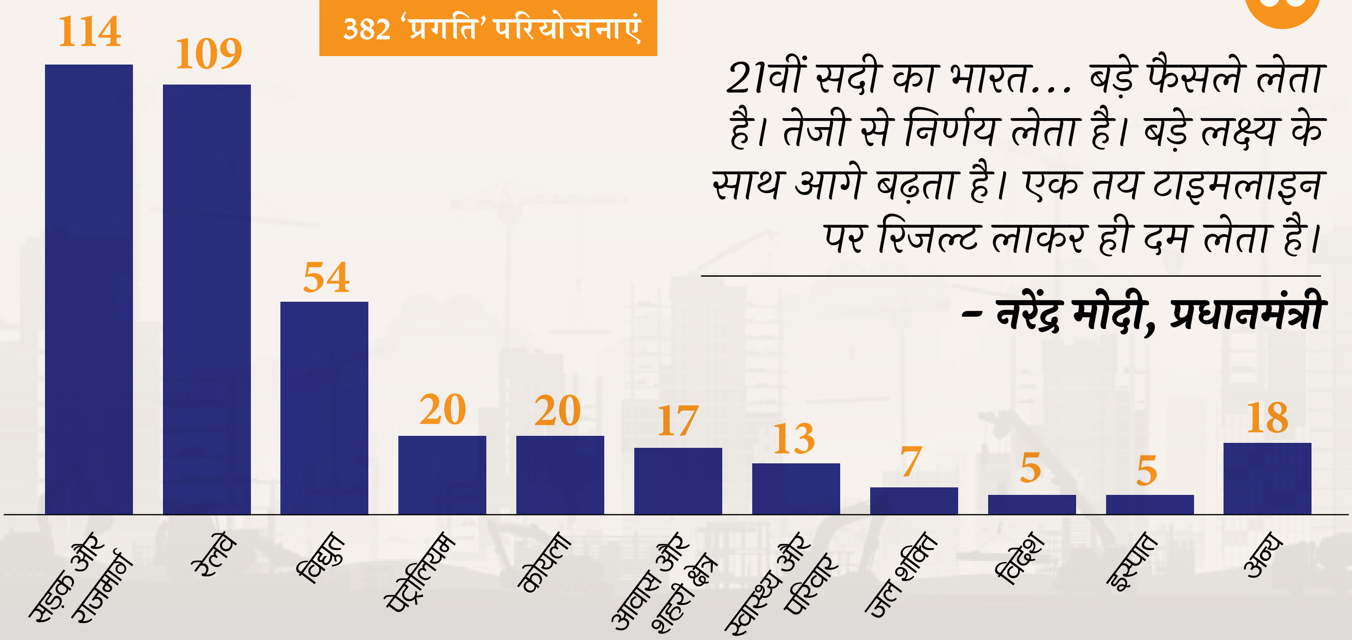

> *21वीं सदी का भारत... बड़े फैसले लेता है। तेजी से निर्णय लेता है। बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है। एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आंदोलन बनाना। आम बजट को नई दिशा देना हो या 'प्रगति' जैसे फोरम से दशकों तक लंबित होने वाली परियोजनाओं को गति देना। युवा-छात्र-खिलाड़ी और लाभार्थियों से सीधा संवाद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लिविंग की बात हो या उपेक्षित किए गए महापुरूषों को उचित सम्मान दिलाना। प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त कर अंतिम छोर तक समयबद्ध डिलिवरी सुनिश्चित करना हो या प्रशासनिक सुधार के लिए मिशन कर्मयोगी और मंत्रालयों-विभागों के बीच बेहतर तालमेल की पहल। दशकों के फासले को खत्म करते हुए एक देश-एक टैक्स (जीएसटी) के रूप में अर्थ क्रांति या जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाना। कभी असंभव या छोटा मानकर नियति के भरोसे छोड़ दी गई उम्मीदें अब साकार हो रही हैं। लीक से हटकर शुरू की गई पहल नए भारत में बदलाव की पटकथा तैयार कर रही है ताकि 2047 में देश जब अपनी आजादी की शताब्दी वर्षगांठ मनाए, तब इन्हीं संकल्पों की सिद्धि उसे दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार करा सके।

निश्चित रूप से विकसित भारत @ 2047 न केवल एक राष्ट्रीय संकल्प है बल्कि एक समयबद्ध लक्ष्य भी है और राष्ट्रीय हित में 'प्रगति' इसे हासिल करने के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में काम कर रहा है। 'प्रगति' की बैठक आज देश के लोगों को एक अधिकार देने का माध्यम बनी है। यह अधिकार कानून में नहीं लिखा है लेकिन सरकारी योजनाएं समय पर पूरी हो यह नागरिकों का अधिकार है। पहले तीन-तीन, चार-चार दशकों से अनेक योजनाएं अटकी हुई थीं। इन्हें पूरा करने का बीड़ा वर्तमान केंद्र सरकार ने उठाया। 'प्रगति' मंच के कारण पारदर्शिता बढ़ी है और कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। तय समय और तय लक्ष्य पर पूरी हो रही योजनाएं, नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आई स्पीड और उनका स्केल, यह तभी संभव हुआ है, जब जमीनी स्तर पर जाकर प्रक्रियाओं को सुधारा गया है और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन विराट प्रयासों के पीछे 21वीं सदी के युवा भारत की अनगिनत आकांक्षाएं हैं। वह आकांक्षाएं जो बुनियादी सुविधा और सुरक्षा के अभाव में पूरी होनी कठिन हैं। 'प्रगति' जैसे प्रभावी मंच से नया भारत उन कठिनाइयों को दूर कर रहा है, युवा सपनों को सामर्थ्य दे रहा है और संकल्प को सिद्ध करने की दृढ़ इच्छाशक्ति से लैस है जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करेगा और 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

आइए आगे जानते हैं 'प्रगति' की कसौटी पर कसी गई कुछ परियोजनाओं के बारे में जिसने विकसित भारत की आधारशिला रख दी है...

परियोजना

ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील रेल सह सड़क पुल

परियोजना की मंजूरी
मार्च 1997

'प्रगति' प्लेटफॉर्म समीक्षा
27 मई 2015

लागत
5,920
करोड़ रुपये

उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
25 दिसंबर 2018

तथ्य

असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल राष्ट्र के लिए आर्थिक और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है।

> *यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है और लोगों को अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिली है।*
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

बोगीबील ब्रिज

असम-अरुणाचल की नई लाइफ लाइन

असम में बोगीबील सेतु परियोजना को 1997 में स्वीकृति मिली और 2 दशक की देरी के बाद वर्ष 2018 में पूरी हुई।

- यह देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना यह पुल इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है।
- 4.94 किलोमीटर लंबे बोगीबील ब्रिज के रास्ते धेमाजी से डिब्रूगढ़ की दूरी मात्र 100 किलोमीटर रह गई है। पहले यह 500 किलोमीटर थी जिसे पूरा करने में 24 घंटे लगते थे।
- यह देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है जिसमें ऊपर सड़क और नीचे रेल मार्ग है। बोगीबील ब्रिज बनाने की मांग 1965 से की जा रही थी। 30 लाख बोरी सीमेंट के साथ इसमें 125 मीटर के 39 गार्डर लगे हुए हैं।

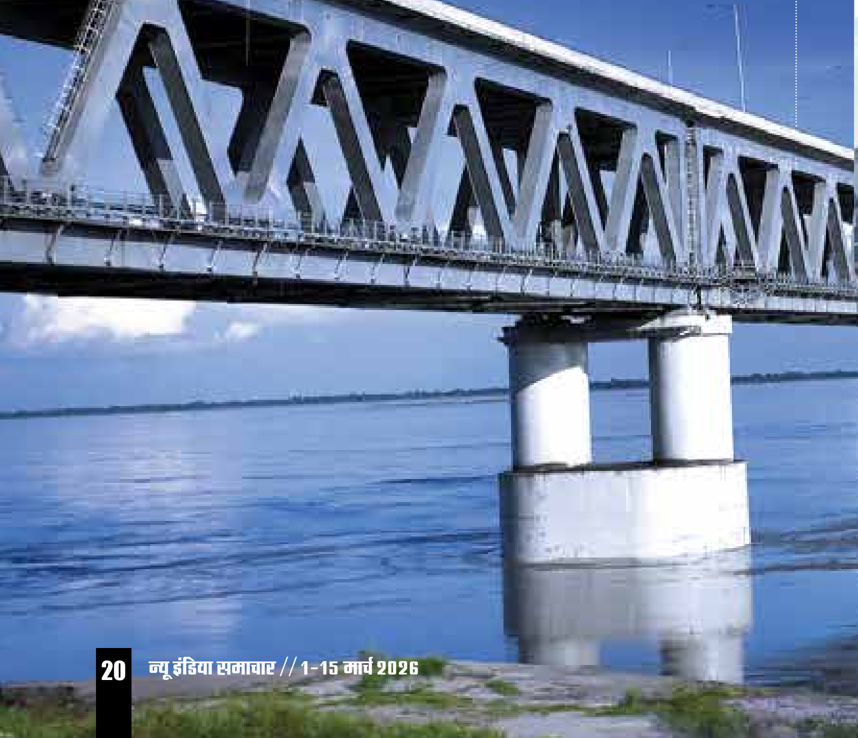

परियोजना

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 4 दशक बाद हुआ तैयार

परियोजना की मंजूरी
वर्ष 1978

परियोजना की लंबाई
318 किमी और लिंकेज 6,590 किलोमीटर

सिंचाई लक्ष्य
14 लाख हेक्टेयर भूमि

उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
11 दिसंबर 2021

बाधा अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव, समुचित निगरानी न होने से परियोजना टलती गई।

> *अगर यह सरकारी पैसा है, तो मुझे क्या परवाह? यही सोच देश के संतुलित और सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। इसी सोच के कारण सरयू नहर परियोजना भी अधर में लटकी रही। हमने सरयू नहर परियोजना में 5 दशक में जितना काम हुआ था, उससे अधिक काम 5 वर्षों में किया है। हमारी प्राथमिकता परियोजना को समय पर पूरा करना है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

- परियोजना की शुरुआत के बाद से 6 बार लागत में संशोधन किया गया। कार्य में देरी की वजह से निर्माण सामग्री, श्रम और भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि हुई।
- परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 1982 में वर्ष 1988-89 रखा गया।
- 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने काम शुरु किया तब उनकी समीक्षा में यह बात सामने आई कि देश की 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थीं। उसी में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना भी थी।
- प्रगति प्लेटफार्म पर दशकों से लंबित परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा के बाद सरयू नहर परियोजना में आ रही रुकावटों का समयबद्ध निवारण किया गया।
- सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का 11 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकार्पण किया।
- परियोजना का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ जिलों- बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के 29 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है।
- परियोजना की शुरुआत 100 करोड़ रु. से भी कम लागत से की गई थी। परियोजना पूरी होने तक इसकी लागत बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई।

परियोजना

पटना : गंगा रेल-सह-रोड ब्रिज

प्रोजेक्ट मंजूरी
5 नवंबर 2001

प्रगति की तारीख
25 मार्च 2015

प्रोजेक्ट की लागत
₹ 3,774 करोड़

प्रोजेक्ट पूरा
3 मार्च, 2022

बाधा
भूमि अधिग्रहण, मुआवजा व पुनर्वास और परियोजना को पूरी तरह से लागू करना

प्रधानमंत्री के निर्देश

- परियोजना में देरी से लागत 5 गुना बढ़ गई। रेलवे लाइन के दोनों तरफ अप्रोच के लिए जरूरी जमीन रेलवे को सौंपी जाए। प्रभावित लोगों को मुआवजा जल्द दिया जाए। उनके पुनर्वास की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए।
- निर्देश के बाद मई 2015 तक उत्तर और दक्षिण दोनों रेल अप्रोच से जुड़ी राइट ऑफ वे की सभी समस्याएं दूर हो गईं।

विकसित भारत... यानी जहां गति भी हो, प्रगति भी हो, जहां लोकहित सर्वोपरि हो... जहां सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाएं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

परियोजना के लाभ

- पटना-गंगा रेल-सह-सड़क पुल (नई लाइन) को जेपी सेतु भी कहा जाता है। इस परियोजना से दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के बीच रेल और सड़क का एक निरंतर और अधिक क्षमता वाला संपर्क मार्ग बन गया।
- करीब 4.55 किलोमीटर लंबे इस संयुक्त रेल-सड़क पुल के बनने से पुराने पुलों पर वर्षों से बना दबाव कम हुआ। सड़क यात्रियों के लिए यात्रा दूरी लगभग 20-25 किलोमीटर कम हो गई।
- पटना शहर के भीतर ट्रैफिक जाम में भी कमी आई। रेल क्षेत्र में भी इस नए पुल से पुराने पुलों पर बोझ कम हुआ। इससे अधिक यात्री और मालगाड़ियों का संचालन संभव हो सका। हर साल करीब 2.78 करोड़ टन माल के परिवहन में मदद मिली।
- पूर्वी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्गों पर ट्रेनों की समय-पालन व्यवस्था बेहतर हुई। साथ ही, गंगा के दोनों किनारों को सीधे जोड़ने से लोगों की पहुंच रोजगार केंद्रों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और बाजारों तक बढ़ी है।
- नए पुल से करीब 149 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है, जो लगभग 6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय लाभ है।

परियोजना

कोसी महासेतु

प्रोजेक्ट को मंजूरी
वर्ष 2003-04

प्रोजेक्ट की लंबाई
1.9 किलोमीटर

लागत
516 करोड़ रुपये

शुभारंभ
18 सितंबर 2020

लाभ

- क्षेत्र के लोगों का 86 वर्ष पुराना स्वप्न साकार हुआ। लंबी प्रतीक्षा पूरी हुई क्योंकि वर्ष 1887 में निर्मली और भापतियाही (सरायगढ़) के बीच एक मीटर गेज लाइन शुरू की गई थी। लेकिन वर्ष 1934 में आई भयानक बाढ़ और भारत-नेपाल में आए भूकंप के चलते यह लाइन तबाह हो गई थी।
- वर्ष 2003 में जब नीतीश कुमार केंद्रीय रेल मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब इस परियोजना की परिकल्पना की गई। उसके बाद व्यवस्था बदली, चाल धीमी हो गई।
- निर्माण पूरा होने से दूरी सिर्फ 22 किमी में सिमट गई है। यात्रा 8 घंटे की बजाय आधे घंटे में पूरी हो रही है।
- उत्तर बिहार के कई जिलों के लोगों के लिए यह मार्ग बेहद लाभकारी हुआ। इससे क्षेत्र के लोगों को कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे लंबी दूरी वाले स्थानों तक जाना और आना सुलभ हुआ।

परियोजना

ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना

ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरीफेरल परियोजना को 2006 में स्वीकृति मिली। परियोजना एक दशक की देरी के बाद 2016 और 2018 में पूरी हुई।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

शिलान्यास
5 नवंबर 2015

उद्घाटन
27 मई 2018

लागत : 11,000 करोड़ रुपये

प्रगति प्लेटफॉर्म

प्रोजेक्ट की समीक्षा में कई सारे पेच पता चले। निरंतर फॉलोअप के बाद कार्य में तेजी आई और बरसों का इंतजार खत्म हुआ।

प्रोजेक्ट की कुल लंबाई : 270 किलोमीटर

- कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली-मानेसर सेक्शन का 19 नवंबर, 2018 को उद्घाटन किया गया।
- शिलान्यास के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 910 दिन का था जो महज 500 दिन में पूरा किया गया।
- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 5,900 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1,700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण।
- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसके पूरे 135 किमी के कॉरिडोर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।
- दिल्ली के आसपास की पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्देश्य दिल्ली को बाईपास कर यहां की भीड़भाड़ को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।

परियोजना

अटल टनल-सामरिक आर्थिक मजबूती का प्रतीक

रोहतांग में मनाली-लेह राजमार्ग पर टनल निर्माण एक दशक से ज्यादा समय से लटका था, जो वर्तमान केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं की वजह से महज छह साल में साकार हुआ। यह टनल भारत के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प का चमकता उदाहरण बना...

परियोजना का शिलान्यास

26 मई 2002

को अप्रोच रोड के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।

2002 में शिलान्यास के बाद से 2013-14 तक महज 1,300 मीटर टनल का काम हो पाया था। उसी रफ्तार से काम होता तो यह 2040 में जाकर पूरा होता।

लागत- 950 करोड़ रुपये थी, देरी के कारण बढ़कर 3,200 करोड़ रुपये पहुंची।

उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

3 अक्टूबर 2020

बाधा

अटल टनल का निर्माण सहज भी नहीं था। टनल के निर्माण में 587 मीटर लंबे नाले के रूप में कठिन समस्या आई। इसमें 8,000 लीटर प्रति मिनट पानी के बहाव ने निर्माण में बाधा डाली। यह समस्या अपने आप में चुनौती थी। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3 हजार श्रमिक और बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर तीन शिफ्ट में काम किया।

क्यों खास है अटल टनल

- अटल टनल बनने से लद्दाख में तैनात भारतीय सेना को काफी मदद मिलती है। अब सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से होती है।
- अटल सुरंग 10,171 फीट की ऊंचाई पर बनी है। रोहतांग के पास से इसे जोड़कर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी राजमार्ग टनल रोड है।
- घोड़े की नाल के आकार में सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल की ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर की है।
- यह टनल सेमी ट्रांसवर्स सिस्टम, स्काडा नियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रणाली से लैस है।

परियोजना

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु

शिलान्यास	24 दिसंबर 2016
परियोजना पूरी होने की तिथि →	31 दिसंबर 2023
लागत ₹20,550 करोड़	उद्घाटन 12 जनवरी 2024

- यह भारत का सबसे लंबी समुद्री पुल परियोजना 'प्रगति' तंत्र में निगरानी के कारण अनुशासित, समयबद्ध आगे बढ़ी।
- यह पुल 21.8 किमी लंबा और 6-लेन वाला है जो 16.5 किमी लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किमी जमीन पर बना है।
- यह मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। साथ ही मुंबई से पुणे, गोवा एवं दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम कर रहा है।
- यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहा है।
- अटल सेतु के निर्माण के दौरान करीब 17 हजार मजदूर भाई-बहनों और 1500 इंजीनियर्स को सीधा रोजगार मिला।
- अटल सेतु में जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के दो बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा-स्टील इस्तेमाल किया है उससे 4 हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है।

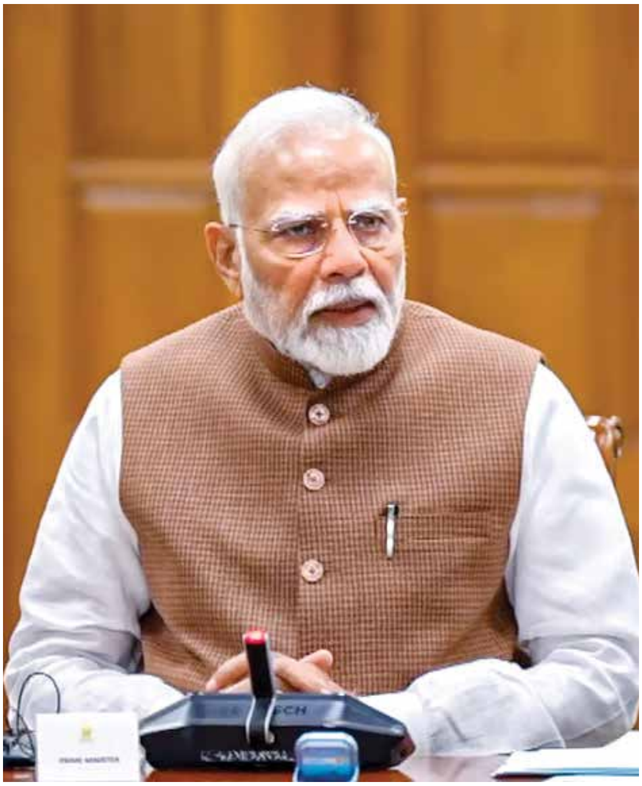

2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है कि बरसों से अटकी-भटकी-लटकी परियोजनाओं को खोज-खोज कर मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। आधी-अधूरी परियोजनाएं हमारे देश के जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे तो बर्बाद करती ही करती हैं, लागत भी बढ़ जाती है और जो उसका लाभ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। ये हमारे टैक्स पेयर्स के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

परियोजना

कोल्लम बाईपास

मंजूरी
1972

केंद्र सरकार की अंतिम अनुमति
जनवरी, 2015

परियोजना की लंबाई
एनएच-66 पर 13 किमी

उद्घाटन
15 जनवरी 2019

लागत
352 करोड़ रुपये

प्रगति प्लेटफॉर्म
करीब चार दशक से लंबित इस परियोजना की अनुमति एवं आर्थिक दिक्कत सहित जो बाधाएं थी, सब समयबद्ध तरीके से प्रगति प्लेटफॉर्म ने दूर की।

लाभ
2 लेन वाली इस बाईपास परियोजना से अलप्पुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हुआ। कोल्लम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हुई है।

परियोजना

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट

प्रोजेक्ट को मंजूरी
6 जुलाई 2007

लागत
₹ 19,646 करोड़

प्रगति पर समीक्षा
25 मार्च 2015,
29 सितंबर 2021

काम पूरा
25 दिसंबर 2025

लाभ
महाराष्ट्र के किसान मध्य पूर्व के सुपर मार्केट से जुड़े

परियोजना

जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर बारामूला रेल लिंक

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) स्वतंत्र भारत में शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में से एक है। हिमालय की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों में 272 किलोमीटर तक फैली इस परियोजना में 119 किलोमीटर सुरंग है। इसमें 38 सुरंग के अलावा घाटी और पहाड़ी दर्रों को जोड़ने वाले 943 पुल शामिल हैं। यह रेल नेटवर्क जम्मू-कश्मीर के लिए गतिशीलता, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ती है।

प्रोजेक्ट को मंजूरी
31 मार्च 1994

लागत
₹ 43,780 करोड़

रेल लाइन की लंबाई
272 कि.मी.

शुभारंभ
6 जून 2025

खासियत
38 सुरंग (लंबाई 119 किमी), 943 पुल

प्रगति पर समीक्षा
24 जून 2015, 6 नवंबर-2019 और 30 दिसंबर-2020

- विश्व का सबसे ऊंचा 359 मीटर रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण हुआ जो चिनाब ब्रिज पर बनाया गया।
- कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी।

परियोजना

खुर्दा-बलांगीर न्यू ब्रॉड गेज रेल लिंक

मंजूरी
31 मार्च 1994

काम की शुरुआत
8 मार्च 2001

लंबाई
301 कि.मी.

प्रगति मंच पर समीक्षा
30 सितंबर 2015, 22 जनवरी 2020

पूरा करने का लक्ष्य
31 दिसंबर 2026

लागत
₹5,089 करोड़

लाभ क्षेत्रीय व्यापार और भुवनेश्वर-बलांगीर के बीच की दूरी कम होगी।

बाधा: वन मंजूरी/ भूमि अधिग्रहण

इस रेल लाइनों पर सभी 7 सुरंग का निर्माण कार्य पूरा

परियोजना

अगरतला-सब्रूम नई रेल लाइन

शिलान्यास
अक्टूबर 2008

प्रगति मंच पर समीक्षा
24 जून 2015

लागत : ₹5,138.51 करोड़

बाधा : वन, वन्य जीव, पर्यावरण

काम शुरू हुआ
29 जुलाई 2009

उद्घाटन
अक्टूबर 2019

लाभ अनाज और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई का खर्च कम हुआ। इससे त्रिपुरा के बाजारों में बिना रुकावट सप्लाई बनी रही और कीमतों में स्थिरता आई।

परियोजना

सीवुड-बेलापुर-उरण लाइन

मंजूरी
11 जुलाई 1997

प्रगति मंच पर समीक्षा
22 फरवरी 2017

लागत
₹2,980.41 करोड़

पूरी होने की तारीख
11 मार्च 2023

लाभ बेलापुर-उरण रेलवे लाइन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सबअर्बन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसे नवी मुंबई के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया।

बाधा: वन, वन्य जीव, पर्यावरण

परियोजना

हरिदासपुर-पारादीप न्यू रेल लाइन

मंजूरी
1 जनवरी 1997

प्रगति मंच पर समीक्षा
29 अगस्त 2018

बाधा: भूमि अधिग्रहण व कुछ अन्य

लागत
₹11,186 करोड़

पूरी होने की तारीख
31 जुलाई 2020

लाभ पारादीप पोर्ट से रेल की 40 कि.मी. दूरी कम हुई। माल ढुलाई की दक्षता में 25 से 30% की वृद्धि। 20 से 25 अतिरिक्त माल वाहक ट्रेन प्रति दिन बढ़ी।

परियोजना

हैदराबाद मेट्रो रेल (72किमी)

मंजूरी
2012

प्रगति मंच पर समीक्षा
31 दिसंबर 2015

लागत
₹ 18,975 करोड़

पूरी होने की तारीख
07 फरवरी 2020

बाधा
बिजली टैरिफ सहित वित्तीय बाधाएं।

लाभ यह पीपीपी मॉडल के तहत विकसित दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो परियोजना है। इसमें मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट का एकीकरण और बड़े पैमाने पर ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट शामिल है, जिससे शहरी यातायात और आर्थिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

परियोजना

अहमदाबाद मेट्रो रेल (फेज-1)

मंजूरी
17 नवंबर 2014

लागत
₹ 12,924.5 करोड़

प्रगति मंच पर समीक्षा
25 अप्रैल 2018, 30 दिसंबर 2020

पूरी होने की तारीख
जनवरी 2026

बाधा: वित समस्याएं, जमीन अधिग्रहण।

लाभ यात्रा के समय में बचत के साथ ईंधन की खपत कम हुई। वायु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ और यातायात सुरक्षा के साथ ही भीड़भाड़ कम हुई।

परियोजना

दिल्ली एमआरटीएस फेज-3

मंजूरी
26 दिसंबर 2011

प्रगति मंच पर समीक्षा
27 मई 2015

लागत
₹ 38,585 करोड़

पूरी होने की तारीख
6 अगस्त 2022

लाभ मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत हुई, दिल्ली-एनसीआर में आवाजाही आसान

बाधा: भूमि अधिग्रहण, लागत शेयर और निर्माण से जुड़ें मुद्दे

परियोजना

गाडरवारा सुपर थर्मल पावर

मंजूरी	आधारशिला	इसमें 800 मेगावाट की दो इकाईयां
2008	2014	

राष्ट्र को समर्पित
अक्टूबर 2025

विलंब की वजह
भूमि, ईंधन लिंकेज और कार्यान्वयन संबंधी समस्या

लाभ मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी राज्यों को निबार्ध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई।

- प्रगति प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के बाद प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार
- मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है एनपीसी की यह प्रोजेक्ट

परियोजना

कुडगी-1 सुपर थर्मल पावर प्लांट, 3X800 मेगावाट, एनटीपीसी

मंजूरी
1 मार्च 2012

प्रगति मंच पर समीक्षा
24 जून 2015

लागत
₹ 18,382 करोड़

पूरी होने की तारीख
3 दिसंबर 2018

लाभ दक्षिण भारत के औद्योगिक इलाकों में बिजली आपूर्ति और दक्षिण भारत में ग्रिड स्थिरता।

बाधा: भूमि अधिग्रहण, इस्तेमाल का अधिकार।

परियोजना

सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन

मंजूरी
1 मार्च 2012

प्रगति मंच पर समीक्षा
30 दिसंबर 2015

लागत
₹ 11,406 करोड़

पूरी होने की तारीख
29 मार्च 2019

लाभ सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करके, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाकर तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को समर्थन देकर महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मूल्य का सृजन किया है।

बाधा: इस्तेमाल का अधिकार / रास्ते का अधिकार, बिजली, फ्यूल और जमीन का अधिग्रहण।

परियोजना

कामेंग हाइड्रो पावर

मंजूरी
नवंबर 2004

प्रगति मंच पर समीक्षा
24 जून 2015

बाधाः जमीन अधिग्रहण, वन, वन्यजीव और पर्यावरण।

लागत
₹ 8,458.95 करोड़

पूरी होने की तारीख
10 फरवरी 2021

लाभ: कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण अरुणाचल प्रदेश देश का पावर-सरप्लस राज्य बन गया। यही नहीं, वह रीजनल और नेशनल ग्रिड को सरप्लस बिजली सप्लाई करने लगा।

परियोजना

पारे जल विद्युत (110 मेगावाट) नीपको लिमिटेड

मंजूरी
26 नवंबर 2008

प्रगति मंच पर समीक्षा
27 दिसंबर 2015

बाधाः वन, वन्यजीव, पर्यावरण और राइट ऑफ वे से जुड़ी समस्याएं।

लागत
₹ 1656.74 करोड़

पूरी होने की तारीख
24 मई 2018

लाभ: पूर्वोत्तर के सेवन सिस्टर्स राज्यों की जल विद्युत क्षमता में बड़ा परिवर्तन। स्वच्छ ऊर्जा के जरिये भारत के बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद।

परियोजना

जयपुर-सीकर-चूरू गेज कन्वर्जन

मंजूरी
2008-09

प्रगति मंच पर समीक्षा
28 सितंबर 2016

बाधाः वन, वन्य जीव, पर्यावरण

लागत
₹ 1,222 करोड़

पूरी होने की तारीख
25 अप्रैल 2019

लाभ: 1,500 मीटर तक लंबाई वाली ट्रेनों के संचालन को सक्षम बनाया। प्रति ट्रेन माल वहन क्षमता लगभग 5,000 मीट्रिक टन से बढ़कर करीब 13,000 मीट्रिक टन हो गई।

जबलपुर-गोंदिया 285 किमी गेज परिवर्तन

मंजूरी
17 जनवरी 2003

प्रगति मंच पर समीक्षा
23 मार्च 2016

बाधाः जमीन अधिग्रहण, वन, वन्यजीव और पर्यावरण क्लीयरेंस से जुड़ी समस्याएं।

लागत
₹ 1,990.98 करोड़

पूरी होने की तारीख
21 मार्च 2021

लाभ: यह परियोजना जबलपुर से बड़े मेट्रो शहरों तक बिना किसी ट्रांसशिपमेंट के पैसेंजर और माल ढुलाई की आसान कनेक्टिविटी देता है, जिससे यात्रा का समय और लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होता है। यह पूर्वी मध्य प्रदेश के आदिवासी और जंगली इलाकों के लिए बाजारों, हेल्थकेयर, शिक्षा और जिला हब तक पहुंच को बढ़ाता है।

परियोजना

2.5 एमएमटी पादुर रणनीतिक कच्चे तेल का भंडारण

मंजूरी
7 जनवरी 2004

प्रगति मंच पर समीक्षा
22 अप्रैल, 2015 और 23 मार्च, 2016

बाधाः राइट टू यूज और राइट ऑफ वे से संबंधित

लागत
₹7,581 करोड़

पूरी होने की तारीख
31 दिसंबर 2018

लाभ पादुर एसपीआर के चालू होने से न केवल सामाजिक आर्थिक फायदे हुए बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी है। इससे कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट और इमरजेंसी से निपटने की भारत की क्षमता मजबूत हुई है।

परियोजना

कुडनकुलम-एपीपी ट्रांसमिशन सिस्टम

मंजूरी
12 मई 2005

प्रगति मंच पर समीक्षा
04 नवंबर 2015

बाधाः राइट ऑफ वे और राइट ऑफ यूज समेत अन्य समस्याएं

लागत
₹2,577.23 करोड़

पूरी होने की तारीख
31 दिसंबर 2019

लाभ स्वच्छ परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देकर बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार किया और महंगी बिजली खरीद को कम किया। भारत के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों का समर्थन किया। साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर समुदाय का भरोसा बढ़ाया।

परियोजना

बेम्बला सिंचाई

मंजूरी
2 अप्रैल 2007

प्रगति मंच पर समीक्षा
25 अक्टूबर 2023

बाधाः जमीन अधिग्रहण, फाइनेंशियल समस्या

लागत
₹2,685.41 करोड़

पूरी होने की तारीख
30 जून 2025

लाभ इस परियोजना के कारण सूखे की संभावना वाले इलाके में खेती अनिश्चितता दूर हुई। फसलों की सघनता बढ़ी और बारिश पर निर्भरता कम हुई।

शहरी कनेक्टिविटी को नई गति और शहरी चुनौती कोष शुरू करने को मंजूरी

केंद्र सरकार रेल, सड़क, मेट्रो, हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नई गति देकर 'विकसित भारत' की मजबूत नींव रख रही है। इसी कड़ी में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में रेलवे लाइनों के विस्तार, गुजरात के एनएच-56, महाराष्ट्र के एनएच-160ए और तेलंगाना में एनएच-167 के चौड़ीकरण के साथ-साथ नोएडा सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो एक्सटेंशन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही, स्टार्टअप फंड, 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड और ब्रह्मपुत्र अंडरवॉटर टनल सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी...

निर्णय : असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दो लेन वाली ट्विन ट्यूब टीबीएम रोड और एक ट्यूब में रेलवे के आधारभूत ढांचे के प्रावधान के साथ नदी के नीचे एक सुरंग निर्माण को मंजूरी। इसकी कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर।

प्रभाव : यह भारत की पहली और विश्व की दूसरी जलमग्न सड़क-सह-रेल सुरंग होगी। इस परियोजना से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इससे माल ढुलाई की दक्षता बढ़ेगी, रसद लागत कम होगी। क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। परियोजना पूर्ण होने पर यह रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। साथ ही इससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास, प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क और व्यापार एवं औद्योगिक विकास के भी नए द्वार खुलेंगें। यह परियोजना लगभग 80 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी।

निर्णय : दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों में अतिरिक्त पटरियां बिछाने की तीन परियोजनाओं को मंजूरी।

प्रभाव : भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 389 किलोमीटर बढ़ेगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 18,509 करोड़ रुपये है। यह 2030-31 तक पूरी होगी। इस दौरान लगभग 2.65 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होगा। इस पहल से यात्रा में आसानी होगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी। तेल का आयात और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। साथ ही स्थायी और सक्षम रेल संचालन में सहयोग मिलेगा।

निर्णय : बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी।

प्रभाव : शहरी चुनौती कोष उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बाजार वित्त, निजी भागीदारी

निर्णय : भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0) की स्थापना को मंजूरी।

प्रभाव : इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है। इसका मकसद देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाना है। योजना बनाने का मकसद दीर्घकालिक घरेलू पूंजी जुटाकर, वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को मजबूत करना है। साथ ही देश भर में नवाचार-आधारित उद्यमिता को समर्थन देकर भारत के स्टार्टअप सफर के अगले चरण को रफ्तार देना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, भारत को दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप देशों में से एक बनाने के लिए करीब एक दशक से किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

और नागरिक-केंद्रित सुधारों का लाभ उठाएगा। इस कोष का उद्देश्य लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु-अनुकूल शहरों का निर्माण करना है ताकि ये शहर देश के आर्थिक विकास के अगले चरण के प्रमुख वाहक बन सके। यह कोष वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक परिचालन में रहेगा, जिसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2033-34 तक बढ़ाई जा सकती है।

> *मंत्रिमंडल ने गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच एक 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। इसमें ब्रह्मपुत्र के नीचे भारत की पहली अंडरवाटर रोड-सह-रेल सुरंग शामिल है। यह परिवर्तनकारी परियोजना असम और पूरे पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, लॉजिस्टिक लागत कम करेगी और विकास को गति देगी।*
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

निर्णय : नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से 'सेवा तीर्थ' तथा 'कर्तव्य भवनों' में स्थानांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति। 'युगे युगेन भारत' राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए मार्ग प्रशस्त।

प्रभाव : 13 फरवरी, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया प्रधानमंत्री कार्यालय जिसे अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया। साउथ ब्लॉक के उस कक्ष में 13 फरवरी को अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। वह केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं बल्कि वह इतिहास और भविष्य के संगम का भी पल बना। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह संकल्प भी लिया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' का हिस्सा बनाया जाए, जो हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता से पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। यह संग्रहालय, हमारी कालातीत और शाश्वत सांस्कृतिक विरासत के उत्सव का प्रतीक होगा और हमारे गौरवशाली अतीत को समृद्ध भविष्य से जोड़ेगा।

निर्णय : महाराष्ट्र में एनएच-160ए के घोटी-त्रिंबक (मोखादा)-जव्हार-मनोर-पालघर खंड के पुनर्विकास और उन्नयन को मंजूरी। इसे पक्की उप-सड़क के साथ 2 लेन/4 लेन के रूप में निर्मित किया जाएगा।

प्रभाव : इसकी कुल लंबाई 154.635 किमी और कुल पूंजीगत लागत 3,320.38 करोड़ रुपये है। यह निर्माण कार्य-इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड में पूरा किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर यह सुचारू और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करेगा। साथ ही, यात्रा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के कार्यान्वयन से जनजातीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। अनुमान है कि इस परियोजना से लगभग 19.98 लाख मानव-दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार और 24.86 लाख मानव-दिवसों का अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा।

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

निर्णय : नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन (नोएडा) तक 11.56 किलोमीटर लंबे और 8 स्टेशनों वाले विस्तार गलियारे को स्वीकृति।

प्रभाव : इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस गलियारे के चालू होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 61.62 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। इसके अलावा यह गलियारा बॉटेनिकल गार्डन (ब्लू लाइन) और मैजेंटा लाइन पर इंटरचेंज सहित अधिकतम मांग वाले गलियारों के साथ सीधी संपर्क सुविधा भी प्रदान करेगा।

निर्णय : गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के धमासिया-बिटाडा/मोवी और नासरपुर-मालोथा खंडों को 4 लेन में परिवर्तित करने की मंजूरी।

प्रभाव : इस परियोजना की कुल लंबाई 107.67 किमी और कुल पूंजी लागत 4583.64 करोड़ रुपये है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-56 का एक हिस्सा है। यह 100 किमी/घंटा की गति के लिए डिजाइन की गई है, 70 किमी/घंटा की औसत गति होगी। इससे यात्रा का समय 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। समय 2.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे हो जाएगा। इससे लगभग 19.38 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 22.82 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।

निर्णय : तेलंगाना में हैदराबाद-पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूबनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-167 को चार-लेन तक चौड़ा करने को मंजूरी।

प्रभाव : इस परियोजना की कुल लंबाई 80.01 किलोमीटर है। इसकी कुल पूंजीगत लागत 3,175.08 करोड़ रुपये है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग (अन्य) योजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग-167 क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रमुख धार्मिक एवं आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क सुदृढ़ होगा। व्यापार एवं औद्योगिक विकास के लिए नए अवसर सृजित होंगे। ▪

'परीक्षा पे चर्चा 2026' कार्यक्रम का एपिसोड-2

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र पढ़ाई और कला दोनों उपयोगी

परीक्षा पे चर्चा 2026 का कार्यक्रम इस बार कुछ अलग, कुछ खास रहा। बहुत सारे छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी कि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। यही कारण है कि इस बार उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में भी छात्रों के साथ बैठ कर परीक्षा पे चर्चा की। 9 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा के दूसरे स्पेशल एपिसोड में उन्होंने कोयंबटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी के विद्यार्थियों से चर्चा की और दिए सफलता के कई मंत्र...

कभी भी शुरू कर सकते हैं स्टार्टअप

जरूरी नहीं, स्टार्टअप के लिए 25 साल की उम्र हो, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे-छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का अध्ययन मंत्र

पढ़ाई और शौक दोनों ही उपयोगी हैं। यह एक-दूसरे के पूरक हैं। कला रचनात्मकता सीखने में मदद कर सकती है और थकान कम कर सकती है। शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी व्यक्तिगत रुचियों के लिए भी समय निकालना जरूरी है।

विकसित भारत में युवाओं का योगदान

कहीं पर भी कूड़ा-कचरा फेंक दिया, यह नहीं चल सकता। अभी यहां पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। हम परिवार में तय करेंगे कि खाने के बाद कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। वोकल फॉर लोकल के तहत अपने देश की चीजें खरीदूंगा। हम सब देश के नागरिक छोटी-छोटी चीजों को करें तो हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं।

प्रेरणा और अनुशासन

जीवन में प्रेरणा और अनुशासन दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो क्या काम आएगा। जीवन में अनुशासन बहुत अनिवार्य है, यह इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है।

टेक्नोलॉजी को समझें

कोशिश होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बनेंगे। हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। खुद का विस्तार करना होगा, उसमें टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा। कार्यों में वैल्यू एडिशन करें। अगर यह होता है तो कितनी ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों न आए, हमें डरने की जरूरत नहीं है।

यात्रा में भारत की विविधता से सीख

हम कहीं पर भी जाए, स्टूडेंट के रूप में जाना चाहिए। तब टूरिज्म का मजा आता है। रेल के डिब्बे में जाना और खासकर साथ में खाना भी ले जाना। देखना चाहिए कैसा अनुभव होता है। भीड़ होती है, क्या होता है, लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक आनंद होता है। जीवन में सीखने को मिलता है। भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, एक जिंदगी भी कम पड़ जाए देखने के लिए।

जो पढ़ा है वो बेकार नहीं गया

आपने जो सुना है, जो पढ़ा है, वो बेकार नहीं गया है। कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए। जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आपको विषय पर ग्रिप होनी चाहिए न, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे।

पीएम मोदी के जीवन में शिक्षक की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन में शिक्षकों की भूमिका के बारे में एक छात्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि शिक्षकों ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके शिक्षक उन्हें प्रतिदिन पुस्तकालय जाने, टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादकीय पढ़ने, उसे लिखने और अगले दिन उस पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इससे उनमें अनुशासन और जिज्ञासा का भाव पैदा हुआ। उन्होंने अपने प्राथमिक विद्यालय के दिनों के परमार सर की यादें साझा कीं जो शारीरिक फिटनेस पर बहुत जोर देते थे। उन्हें योग व मल्लखंब सिखाते थे। भले ही वे पेशेवर खिलाड़ी नहीं बन पाए लेकिन इससे उन्हें स्वास्थ्य का महत्व समझ में आया। उन्होंने कहा कि हर महान व्यक्तित्व के जीवन में दो प्रमुख प्रभाव हमेशा याद रखे जाते हैं- एक उनकी माता का और दूसरा उनके शिक्षक का।

हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और कुछ न कुछ सीखना

परीक्षा की बात के साथ-साथ लोकल संगीत, असम की चाय, वो भी परीक्षा पे चर्चा का यादगार हिस्सा बन गई। इस एपिसोड में सभी चर्चाओं में स्थान अलग-अलग था। छात्र अलग-अलग थे और अनुभव भी अलग थे। लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था। हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखना।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पढ़ाई और खेल में संतुलन कायम रखना

जीवन और समाज दोनों में शिक्षा की जरूरत है। इसको अंडर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए। यह गलती कभी मत करना कि मैं खेल में बहुत अच्छा हूं, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी, ऐसा नहीं है। आप में हुनर है, जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेलें वो एक विषय है लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है।

पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए हमारा स्वभाव

प्राकृतिक संपदा को बचाना हमारे स्वभाव में होना चाहिए और धीरे-धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। मानवीय रूप से व्यवहार करें तो बदलाव शुरू हो जाता है।

लीडर रोल में तैयार करना चाहिए

जो काम है मन में तय करिए। कोई करे या न करे मैं करूंगा। जब यह आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। लेकिन लीडर का मतलब यह नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छेदार भाषण करना। लीडर मतलब, लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का विकास

गुजरात में पाल-चितरिया के आदिवासी समाज ने बहुत बड़ा आजादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा था तो उस समय मैंने उस क्षेत्र में काफी दिनों तक रहकर काम किया था। उस समय लगता था कि यहां एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। अब तो दो यूनिवर्सिटी हैं, साइंस स्कूल हैं, आईटीआई है, बहुत सारा बदलाव आया है। उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है।

तुलना से बचें माता-पिता

मां-बाप को तुलना से बचना चाहिए। मैं हर माता-पिता से कहता हूं कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि बच्चे की आदत खराब हो जाए। एक बच्चे की इतनी तारीफ न करें कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते हैं, मेरी तो बताते नहीं।

हर चीज कर सकते हैं आप

अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। जिसको खुद पर विश्वास होता है करता क्या है? पूरी परिस्थिति का मन ही मन अध्ययन करता है। हम जो स्थिति है उसको ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को एक बार अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ऐसा हुआ था। अब देखना आपको लगेगा हां अरे ठीक है मैं कर लूंगा। जो आत्मविश्वास शब्द है न उसको सच्चे अर्थ में जीवन में समझना है। आत्म की बात, खुद की बात है। कोई ठीक नहीं करता है, हमें ही करना होता है। ■

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, पीएम मोदी का जवाब

अब आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा भारत

आज मेरा देश पूरा सामर्थ्य दिखा रहा है। यह तब होता है जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके नागरिकों में देश के प्रति ऊर्जा हो और खासकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तभी विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान 5 फरवरी को जवाब देते हुए राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था, व्यापार समझौतों समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। करीब डेढ़ घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त किया और कहा अब भारत पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा। प्रस्तुत है संबोधन के संपादित अंश...

पिछले एक साल में हुई तेज प्रगति

पिछला साल विकसित भारत की यात्रा में तेजी से प्रगति का रहा है, जिसमें हर क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों में बदलाव साफ दिख रहा है। देश बहुत तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने इन विषयों को संवेदनशीलता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति ने इस मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, गांव, किसान, महिला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, सभी विषयों को लेकर बहुत ही विस्तार से भारत की प्रगति का एक स्वर संसद में प्रस्तुत किया है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी विस्तार से चर्चा की है।

तेजी से आगे बढ़ना है, लक्ष्य हासिल करना है

21वीं सदी का पहला क्वार्टर खत्म हो गया है। जिस तरह पिछली सदी का दूसरा क्वार्टर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक था, उसी तरह यह दूसरा क्वार्टर भी विकसित भारत बनाने में उतना ही शक्तिशाली और तेज गति वाला होगा। हर नागरिक महसूस करता है कि देश एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां रुकने या पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, बस तेजी से आगे बढ़ना है। लक्ष्य हासिल करना है और उसे पाने के बाद ही चैन की सांस लेनी है और इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है।

युवा आबादी वाला देश

वर्तमान में हम देखें तो भारत के भाग्य के अनेक सुयोग एक साथ हमें नसीब हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है, हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते थे। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसी समय दिनों-दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। उसमें भी विश्व भारत के टैलेंट का माहात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है और सामर्थ्य भी है।

आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत

आज कोई भी सेक्टर देख लीजिए चाहे साइंस हो, स्पेस हो, स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। विश्व मित्र के रूप में, आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला कर, विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं।

रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र

हम रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। हमने स्ट्रक्चरल, प्रोसेस से जुड़े और पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उद्यमी सशक्त हो, भारत

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा भारत

आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, भारत उन चुनौतियों का समाधान देने वाला आशा की किरण बना हुआ है। जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब '**Fragile Five**' के रूप में यह देश जाना जाता था। देश आजाद हुआ तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे लेकिन ऐसा हाल हुआ कि 11 पर पहुंचा दिया। आज हम तीन पर जाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

छोटे किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपये दिए

हमारे दिल में छोटे किसान के प्रति एक दर्द था। हम जमीनी हकीकत से परिचित थे। उसी के कारण हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर आए। इतने कम समय में हमने छोटे किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। जिसने हमारे छोटे किसानों को एक नई ताकत दी है। नए सपने देखने का सामर्थ्य दिया है। मुझे यह पक्का विश्वास है कि हमारा किसान उस दिशा में जरूर भारत की आशा-अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देगा।

की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किए हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

MSMEs नेटवर्क पर बढ़ रहा दुनिया का भरोसा

MSME का बहुत बड़ा नेटवर्क जितना सामर्थ्यवान होता है, वह लंबे अरसे तक इकोनॉमी को एक ताकत देता है। हमने उस दिशा में बल दिया है और कई रिफॉर्म्स किए हैं। आज हमारे MSMEs नेटवर्क पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। हम हवाई जहाज नहीं बनाते होंगे, लेकिन कई हवाई जहाज हैं, जिसमें कई पुर्जे मेरे देश के छोटे से छोटे MSMEs बनाते हैं।

बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा

बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा और अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहा है। हमने मुद्रा योजना के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लोन देश के नौजवानों के हाथ में दिए। वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार तो किया ही किया, साथ में 10 करोड़ बहनों को सीधी आर्थिक मदद की व्यवस्था की। आज एनपीए एक परसेंट से भी नीचे है, यह अपने आप में बैंकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम काम किया है। इतना ही नहीं, बैंकों का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड पर है। यह अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है, तो बाकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत मिलती है, उस काम को किया है। PSUs के संबंध में भी रिफॉर्म्स किए। आज हमारे PSUs को बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर देश से भी और देश के बाहर से भी मिलने लगे हैं।

> *मेरे देश के युवा का हमें गौरव करना चाहिए, उनके लिए पूरा विश्व बाजार अब खुल चुका है। अब उनके लिए अवसर ही अवसर है। मैं उनको कहता हूं, आइए दोस्तों मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, हिम्मत कीजिए आगे बढ़िए, देश आपके साथ खड़ा है।*
>
> **–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

140 करोड़ समाधान हमारे पास

हमारी सोच है कि 140 करोड़ देशवासी इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो चुनौतियों का समाधान दे सकते हैं। हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है और यही लोकतंत्र की भी सच्ची ताकत होती है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्ज्वल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, कर्ता-धर्ता है।

2047 तक बनना है विकसित भारत

हम विकसित भारत का सपना लेकर चले हैं और आज वो सपना देश के लोगों की ऊर्जा के कारण संकल्प में बदल चुका है। आज कहीं पर भी जाइए हर कोई यह कहता है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। विपक्ष के समय में,

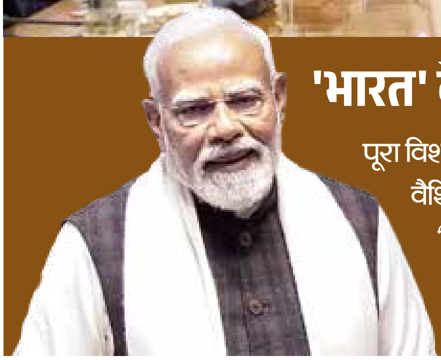

'भारत' वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज

पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ भारत 'फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स' कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें "**Mother of all Deals**" एक साथ 27 देश के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ।

'भारत ने मौका गंवा दिया' यह मुहावरा आम था, जो छूटे हुए अवसरों का प्रतीक था। आज, भारत कोई मौका नहीं गंवा रहा है, बल्कि अब वह आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा।

मेरा देश अजर-अमर रहने वाला

देश का भविष्य उज्ज्वल बनाना है। वर्तमान को भी उज्ज्वल बनाने के लिए अविरत कार्य करना होता है। हम विकसित भारत के सपने के फ्लाइट में 5 वर्ष की योजना और हर वर्ष का बजट बनाते हैं। हम दिशा तय करके चलते हैं। क्योंकि देश अजर-अमर रहने वाला है। हम देश की युवा पीढ़ी के हाथ में समृद्ध हिंदुस्तान देने का सपना लेकर चले हैं। घर में जो बालक है न, उनको देखकर सोचता हूं कि मैं इसके हाथ में ऐसा हिंदुस्तान देकर जाऊं, ताकि हमें अपने काम का संतोष हो।

नई सिद्धियों को लेकर आज देश बढ़ रहा है आगे

आज जिस प्रकार से हमने इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे स्पेस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, समंदर की गहराई हो, जल-थल-नभ, हर क्षेत्र में नए संकल्प, नई ऊर्जा, नए कदम और नई सिद्धियों को लेकर देश आज आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले युग को समझ पा रहे हैं। हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। हम एआई मिशन को लेकर चल रहे हैं। आज दुनिया में क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ राजनीतिक हथियार बन गया है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं।

आने वाला समय भारत के लिए अवसरों से भरा

आने वाला समय भारत और उसके नौजवानों के लिए अवसरों से भरा हुआ है। मैं देख सकता हूं और उस दिशा में नीतियां बना कर हम आगे चल रहे हैं। मेरे देशवासियों से मैं आज यही आग्रह करूंगा कि आप क्वालिटी के विषय में मेरा साथ दीजिए। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज न करिए। आप देखिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, इसके लिए गीत गाने लग जाएगी।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का जवाब देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सुधार एक्सप्रेस पर सवार भारत

...इसलिए पूरी व्यवस्था बदलने पर हुआ काम

भारत के लिए यह दशक अभूतपूर्व विकास, बेहतर कामकाज और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला रहा है। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। भारत ने 2015 में ही नीति आयोग के दस्तावेज में स्पष्ट किया था कि देश किसी भी विदेशी विकास मॉडल को नहीं अपनाएगा बल्कि अपनी जरूरत और अनुभव के अनुसार अपना रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 में कहा कि मजबूरी में किए सुधार कभी भी सही परिणाम नहीं देते, इसलिए सरकार ने पूरी व्यवस्था बदलने पर किया काम...

नया भारत जिस विकास के दृष्टिकोण पर आगे बढ़ रहा है उस नीति ने देश को अपनी जरुरतों और हितों के मुताबिक फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया है। यही कारण है कि उथल-पुथल भरे इस दशक में भी भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई, बल्कि लगातार मजबूत होती रही। ईटी नाउ ग्लोबल समिति 2026 में 'व्यवधानों का दशक, परिवर्तन की शताब्दी' विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने समय में बनाए जाने वाले कैबिनेट नोट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट नोट तैयार करने में पहले हफ्तों या महीनों लग जाते थे, जिससे विकास की रफ्तार धीमी रहती थी। उनकी सरकार

संबोधन के कुछ मुख्य बिंदु

- भारत की आर्थिक शक्ति में वृद्धि के साथ-साथ सरकार ने राज्यों को भी सशक्त बनाया है। 2004 से 2014 तक राज्यों को कर हस्तांतरण से लगभग 18 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि 2014 से 2025 तक 84 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। इस वर्ष के बजट की राशि जोड़ दें तो राज्यों को कुल कर हस्तांतरण लगभग 100 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
- 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को कंपल्शन में नहीं... बल्कि कनविक्शन के साथ, रिफॉर्म के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं।
- बजट को न केवल व्यय-केंद्रित बनाया गया बल्कि परिणाम-केंद्रित भी बनाया है। 2014 से पहले ऑफ बजट बॉरोइंग पर बहुत अधिक चर्चा होती थी, लेकिन अब ऑफ बजट रिफॉर्म्स पर चर्चा होती है।
- बजट से बाहर, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया। बजट में घोषित हों या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है।
- बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ, देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर को प्रमोट किया गया है।

जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो हर निर्णय और नीति देश के हित में होती है। सरकार का दृष्टिकोण साफ है, भारत को विकसित बनाने की दिशा में निरंतर काम करना। चाहे आज की पीढ़ी 2047 तक रहे या न रहे, राष्ट्र और उसकी आने वाली पीढ़ियां तो रहेंगी ही। इसलिए वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए स्वयं को समर्पित करे।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित बनाया, ताकि फाइलें अनिश्चित काल तक लंबित न रहें और इसके परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर 21वीं शताब्दी के पिछले दशक में कई व्यवधान देखने को मिले, जिनमें वैश्विक महामारी, विभिन्न क्षेत्रों में तनाव और युद्ध एवं आपूर्ति श्रृंखला में आईं बाधाएं शामिल हैं। इन चुनौतियों ने वैश्विक संतुलन को हिला कर रख दिया। इन व्यवधानों के बावजूद, इस दिशा में यह दशक भारत के लिए उल्लेखनीय विकास, उत्कृष्ट प्रदर्शन और लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण से भरा रहा है। इस पर पीएम मोदी ने गर्व व्यक्त करने के साथ कहा कि मुश्किल भरे वक्त में ही किसी देश की वास्तविक शक्ति सामने उभर कर आती है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था, तब भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी लेकिन आज भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वर्तमान में भारत वैश्विक विकास में 16% से अधिक का योगदान देता है। इस पर प्रधानमंदी मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह योगदान वर्ष दर वर्ष बढ़ता रहेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों पर वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा और विश्लेषण हो रहा है, लेकिन 2014 से पहले ऐसे समझौते क्यों संभव नहीं थे। देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव, सरकार के विजन में आया है, नीति और नीयत में आया है, भारत के सामर्थ्य में आया है। पिछले एक दशक में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों के 38 देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा है, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। पिछले 11 सालों में भारत में एक मजबूत विनिर्माण प्रणाली विकसित की गई है। यह भारत की व्यापार नीति में एक अहम बदलाव का आधार बना है और विकसित भारत की ओर यात्रा का एक अनिवार्य स्तंभ बन गया है। आज देश समर्थ है, सशक्त है और इसलिए दुनिया भी भारत पर भरोसा करती है। ■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पीएम मोदी का असम दौरा

सुरक्षा और विकास का नया अध्याय

पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए अष्टलक्ष्मी है। यही कारण है कि केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग पचास हजार करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा और विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम पहुंचे और राज्य को दी कई अहम विकास परियोजनाओं की सौगात...

देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे एवं टनल्स, ऊंचे-ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड बना रहा है और देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। असम दौरे के दौरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर उतरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत, अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। भारत अब न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है।

कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया।
- गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ने वाला यह 6-लेन का एक्स्ट्राडोज्ड प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल, पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है।
- इससे गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 7 मिनट रह जाएगा।
- इस क्षेत्र की उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता को देखते हुए, पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग्स का उपयोग कर बेस आइसोलेशन तकनीक को अपनाया गया है।
- पुल के स्थायित्व और दीर्घकालिक संरचनात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले स्टे केबल्स का उपयोग किया गया है।
- इसके अलावा, रियल-टाइम कंडीशन मॉनिटरिंग, क्षति का शीघ्र पता लगाने और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को भी शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

यह अत्यंत गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा मिली है। स्ट्रेटेजिक दृष्टि से और प्राकृतिक आपदाओं के समय, यह सुविधा बहुत महत्व रखती है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा

आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इसे भारतीय वायुसेना के समन्वय से विशेष रूप से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में कार्य करेगी। इससे पूर्वोत्तर में प्राकृतिक आपदाओं या रणनीतिक आवश्यकताओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों की त्वरित तैनाती संभव हो सकेगी। दोहरे उपयोग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में परिकल्पित यह ईएलएफ, 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन के अधिकतम टेक-ऑफ वजन वाले परिवहन विमानों के संचालन में सक्षम है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन

- असम के कामरूप जिले के अमिंगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन।
- यह अत्याधुनिक डेटा केंद्र, जिसकी कुल स्वीकृत क्षमता 8.5 **MW** और प्रति रैक औसत क्षमता 10 **kW** है। यह विभिन्न सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण मिशन-क्रिटिकल एप्लिकेशन को होस्ट करेगा।
- यह अन्य राष्ट्रीय डेटा केंद्रों के लिए डिजास्टर रिकवरी केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा।
- इससे पूर्वोत्तर की सरकारों को आवश्यक नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- इस राष्ट्रीय डेटा केंद्र को क्षेत्र के आईसीटी ढांचे को मजबूत करने और एक सुदृढ़, सुरक्षित और निरंतर उपलब्ध रहने वाला डिजिटल बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित किया गया है।
- पीएम मोदी ने आईआईएम गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

- पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत गुवाहाटी (100), नागपुर (50), भावनगर (50) और चंडीगढ़ (25) में कुल 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- इन चार शहरों में पीएम ई-बस सेवा के संचालन के शुभारंभ के साथ ही, 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ मिलेगा।
- यह पहल शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाइवे और अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये देना तय हुआ है। बजट में जो घोषणा हुई है, उससे असम में पर्यटन का भी विस्तार होगा। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 के बाद, नॉर्थ ईस्ट के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह दिखाता है कि असम और पूर्वोत्तर की धरती का सामर्थ्य कितना बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का यही सामर्थ्य अब विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। ▪

"इंडिया एआई इंपैक्ट समिट-एक्सपो 2026"

नए विचार, नवाचार और इरादों का सशक्त संगम

भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। इसी दिशा में आयोजित 'इंडिया एआई इंपैक्ट समिट और एक्सपो 2026' देश की तकनीकी क्षमता, नवाचार और डिजिटल बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मिलकर ऐसे समाधान तैयार करेंगे, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी उपयोगी...

वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला यह पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है, जिसमें अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट और एक्सपो-2026 यह दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विनिर्माण, खेल-खिलौने और सुशासन जैसे क्षेत्रों में वास्तविक बदलाव ला रहा है। विकसित भारत के संकल्प के साथ यह एक्सपो उस सोच को सामने लाता है, जिसमें तकनीक का इस्तेमाल समावेशी विकास, पारदर्शिता और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि एआई के व्यावहारिक उपयोग का मंच है, जहां नीतियां जमीन पर उतरती हैं, नवाचार बड़े पैमाने पर लागू होते हैं और तकनीक का लाभ आम नागरिक तक पहुंचता है।

AI IMPACT SUMMIT
भारत 2026 INDIA

एआई एक्सपो और समिट की मुख्य झलकियां...

20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष **60** मंत्री और 500 वैश्विक एआई लीडर एकत्रित हुए।

- एआई इंपैक्ट समिट तीन मूलभूत स्तंभों या 'सूत्रों' पर आधारित है-लोग, ग्रह और प्रगति।
- 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरेना में आयोजित यह समिट वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लाया।
- इस एक्सपो में एआई तंत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के पवेलियन बने थे। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं।
- एक्सपो में 300 से अधिक चुनिंदा प्रदर्शनी मंडप और लाइव प्रदर्शनी हुई।
- एक्सपो में 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप शामिल हुए जिनमें से कई वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और व्यापक जनसंचार समाधान कर रहे हैं। ये स्टार्टअप ऐसे उपयुक्त समाधानों का प्रदर्शन करेंगे जो पहले से ही वास्तविक दुनिया में उपयोग में हैं।
- समिट एआई इंपैक्ट 2026 में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 2.5 लाख से अधिक आगंतुकों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया।
- आयोजन का उद्देश्य वैश्विक एआई तंत्र के भीतर नई साझेदारियों को बढ़ावा देना और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करना रहा।
- समिट के दौरान कुल 500 से अधिक सत्रों का आयोजन हुआ जिसमें 3,250 से अधिक वक्ता और पैनल सदस्य शामिल हुए।

"

भारत अपनी 140 करोड़ जनता की बदौलत एआई परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम और अत्याधुनिक अनुसंधान तक, एआई में हमारी प्रगति महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक्सपो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारतीय प्रतिभा और नवाचार की ताकत को दिखाता है। उन्होंने बताया कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति देश के लिए नए और बदलावकारी समाधान तैयार करेगी। साथ ही, वैश्विक विकास में भी अहम योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने दुनिया के सामने फिर से साबित किया है कि भारतीय प्रतिभा एआई के भविष्य को दिशा देने में सक्षम हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ है कि भारत एआई का उपयोग जिम्मेदारी और समावेशी तरीके से, मानव कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

...ताकि विकास की प्रेरक शक्ति बन नेतृत्व करे आधी आबादी

आज भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को प्राथमिकता दे रही है। सरकार की हर योजना में महिलाओं के सम्मान के साथ-साथ उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण को शामिल किया जा रहा है। क्योंकि सरकार मानती है कि देश के तेज और सतत विकास में आधी आबादी की समान भागीदारी बेहद जरूरी है। जिस देश में अधिक महिलाएं कार्यबल का हिस्सा बनती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था होती है उतनी ही मजबूत...

महिलाओं की समान भागीदारी और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दुनिया 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम- 'सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए-अधिकार, न्याय और कार्रवाई' है। लैंगिक भेद के बिना सभी को अधिकार और न्याय मिले। कोई भी पीछे न छूटे। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का न सिर्फ विस्तार कर रही है बल्कि उनके साथ न्याय हो, इसके लिए हर स्तर पर कार्रवाई भी कर रही है। उनकी आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नई योजना और अनेक पहल की शुरुआत बीते एक दशक में की गई है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के जिस लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है।

देश की आईटीआई में 30 फीसदी सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित किया गया, सैनिक स्कूल के दरवाजे लड़कियों के लिए खोले गए और एनडीए में लड़कियों की एंट्री दी गई। साथ ही विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 में कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाने के प्रावधान से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 की अधिसूचना और प्रधानमंत्री आवस योजना में महिलाओं के नाम घर आवंटन, सभी प्रावधान महिलाओं के अधिकार को मजबूती दे रहे हैं। सरकार के प्रयास का ही नतीजा है कि आज महिलाएं भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सरकार के इन प्रयासों से बढ़े महिलाओं के अधिकार

- **राजनीति में बढ़ेगी भागीदारी:** नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान में 106 संशोधन) अधिसूचित। इसके तहत लोकसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों में विधानसभा की 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- **रोजगार में नहीं होगी अनदेखी:** विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)(वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 में यह अनिवार्य किया गया है कि योजना में सृजित रोजगारों में से कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाएं।
- **बन रही हैं गृह स्वामिनी:** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण महिलाओं के स्वामित्व वाले घर देने पर केंद्रित है। यह निर्णय लिया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर घर का आवंटन महिला के नाम पर या पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से किया जाएगा।
- **उच्च पद पर बैठने का रास्ता:** कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अहर्ताएं) नियम, 2014 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी जिसकी पूंजी 100 करोड़ से अधिक है या कुल कारोबार 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तो कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य है।
- **स्थानीय सरकार में भागीदारी बढ़ी:** प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों और अध्यक्षों के पदों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई (33%) आरक्षण अनिवार्य है। इससे आगे बढ़कर 21 राज्य व दो केंद्र शासित प्रदेशों ने 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी हैं। वर्तमान में पंचायत में निर्वाचित 24,41,741 प्रतिनिधियों में से 12,14,885 (49.75%) महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण व न्याय के लिए एक्शन

- **न्याय संहिता :** भारतीय न्याय संहिता, 2023 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को एक जगह किया गया है। महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध की सजा को सख्त किया गया।
- **कार्यस्थल पर सहायक माहौल:** महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के उद्देश्य से वेतन संहिता, औद्योगिक श्रम संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता में अनेक सहायक प्रावधान किए गए हैं।
- **स्वास्थ्य पर दे सकें अधिक ध्यान:** 26 सप्ताह किया गया सवैतनिक मातृत्व अवकाश 2017 में, उससे पूर्व में 12 सप्ताह का था।
- **कामकाज में निवास की दिक्कत दूर:** 560 सखी निवास यानी कामकाजी महिला छात्रावास देशभर में कार्यरत हैं।
- **संकट में पुनर्वास:** 413 शक्ति सदन देश भर में कार्यशील हैं। यह संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास केंद्र है। 13 हजार महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
- **बच्चे की केयर:** 14,599 आंगनवाड़ी सह क्रेच केंद्र स्वीकृत, 2,820 केंद्र देशभर में कार्यशील हैं।
- **ग्रामीण आजीविका:** 10.29 करोड़ महिलाएं, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं जो देश की ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं।
- **मेहनत और देखभाल बोझ हो कम:** 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का स्वच्छ भारत मिशन में निर्माण, 10.49 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, 15.79 से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन में नल कनेक्शन से जोड़ने के कार्य ने महिलाओं के जीवन को बदलने में सहायता की है।
- **ताकि बढ़े और पढ़े बेटी:** 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य लिंग आधारित लिंग चयन जन्म को रोकना, बालिका का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हुआ। स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2024-25 में 80.2% हुआ।
- **भविष्य हो सुरक्षित:** 22 जनवरी, 2015 को सुकन्या समृद्धि खातों की शुरुआत की गई जिसमें 21 वर्ष की आयु में खाते मैच्योर होंगे। जनवरी, 2026 तक 4.53 करोड़ खाते खोले गए जिनमें 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा है।
- **पोषण भी, पढ़ाई भी:** 10 मई 2023 को शुरू इस कार्यक्रम के लिए 10 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सेविका को प्रशिक्षण दिया गया ताकि बाल्यावस्था में शिक्षा और पोषण ठीक हो। देश भर में 2.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी विद्यालयों में स्थापित किए गए।
- **बाल विवाह से मुक्त हो भारत:** 27 नवंबर, 2024 को भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। जागरुकता कार्यक्रम 6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचा और बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर 28 लाख से अधिक शपथ ली गई।

महिला सशक्तीकरण के लिए की गई पहलें

- वर्ष 2022-23 से 'मिशन शक्ति' योजना कायान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करना है।
- 'संबल' उप योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत शामिल है।
- 'सामर्थ्य' उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प-महिला सशक्तीकरण केंद्र शामिल है।

...ताकि कौशल से लैस हों लड़कियां व महिलाएं

- कौशल भारत मिशन के तहत देशभर में कौशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें प्रशिक्षण के लिए महिलाएं भी बढ़-चढ़ कर शामिल हो रही हैं।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और आईटीआई द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत बीते दशक में 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित किए जाने वाले कुल प्रशिक्षुओं में महिलाओं की भागीदारी 45 फीसदी से अधिक तो जन शिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी 83 फीसदी रही है।

3,327 सक्रिय महिला पायलट की संख्या है 31 दिसंबर, 2025 तक।

वर्ष 2021 (243) की तुलना में 2025 (461) में करीब 90% अधिक लाइसेंस दिए गए।

यहां झलकती है महिलाओं की आर्थिक समावेशिता

56% प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता।

54% बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।

51% बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।

82% लोन, स्टैंड अप इंडिया।

67% लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आंकड़ों के अनुसार, बीते 5 वर्ष के दौरान खुदरा क्षेत्र में महिला उधारकर्ताओं की भागीदारी 2.14 गुना और एमएसएमई क्षेत्र में 2.62 गुना बढ़ी है।

2.94 करोड़ महिला के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देशभर में पंजीकृत हैं।

3 गुना से ज्यादा हुआ 6 साल में जेंडर बजट

वर्तमान केंद्र सरकार महिला नेतृत्व में विकास को गति दे रही है जिसके लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और बजट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 2026-27 के बजट में महिला और लड़कियों के कल्याण के लिए बजट में 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

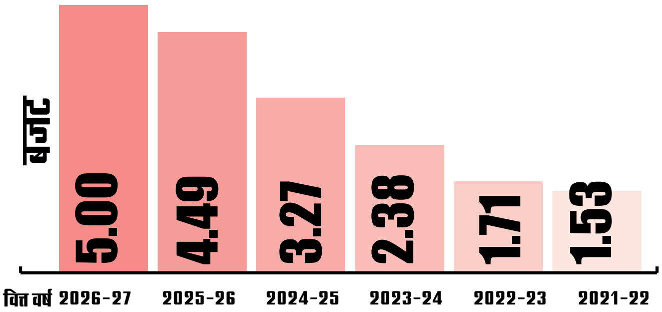

नोटः आंकड़े लाख करोड़ रुपये में।

2026-27 के बजट में महिलाओं के लिए खास

- 1.5 लाख बहु कौशल देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव 2026-27 के बजट में किया गया है जिससे बुजुर्गों, बच्चों और संबंधित देखभाल सेवाओं की डिलीवरी बेहतर होगी।
- स्वयं सहायता उद्यमी (SHE) मार्ट्स की स्थापना की जाएगी। ये समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित और स्थायी मार्केट पहुंच प्रदान करेंगे।
- उच्च शिक्षा में समानता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एसटीईएम संस्थानों में लड़कियों के हॉस्टल का प्रावधान किया गया है। उभरते और टेक्नोलॉजी-आधारित क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

पीएम मोदी ने महिलाओं को सौंप दिए थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च, 2025 को महिला दिवस के अवसर पर भारत भर में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन महिलाओं को सौंप दिए थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रही हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था, "ये महिलाएं भारत के विभिन्न भागों से हैं और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है लेकिन इनमें अंतर्निहित है - भारत की नारी शक्ति का कौशल। उनका दृढ़ संकल्प और सफलता हमें महिलाओं की असीम क्षमता की याद दिलाती है। आज और प्रतिदिन, हम विकसित भारत को आकार देने में उनके योगदान का सम्मान करते हैं।"

> *मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिजम के लिए ग्रैटिस ई-वीजा और डिजिटल पेमेंट इंटरफेस UPI का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम, दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी साझेदारी तभी ताकत से सफल होती है, जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे।*
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भारत-मलेशिया

मैत्री से रणनीतिक साझेदारी तक

भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1957 में हुई थी। तब से दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित रहे हैं, जिन्हें अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया। इन्हीं संबंधों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया की यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए कई महत्वपूर्ण समझौते...

भारत और मलेशिया के ऐतिहासिक संबंधों में हाल के वर्षों में निरंतर प्रगति हुई है जिसमें मलेशिया में रह रहे करीब 30 लाख प्रवासी भारतीय की महत्वपूर्ण भूमिका है। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 के बाद यह तीसरी यात्रा रही। प्रधानमंत्री मोदी की इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिए राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा, सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, आर्थिक और नवाचार के अलावा कुछ नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर विस्तृत बातचीत हुई। यही नहीं पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। यह यात्रा भारत-मलेशिया संबंधों को मजबूत करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हिंद-प्रशांत विजन और विजन महासागर का एक प्रमुख स्तंभ है।

इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया के सदियों पुराने संबंधों और प्रगाढ़ जन-संपर्क को याद किया जो इस साझेदारी की आधारशिला हैं। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने संसदीय और यूनिवर्सिटी एक्सचेंज के माध्यम से युवाओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करने का आह्वान किया। मलेशिया में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास के खुलने से वाणिज्यिक और जन-संपर्क संबंधों को और मजबूती मिलेगी। 10वें भारत-मलेशिया सीईओ फोरम के आउटकम डॉक्यूमेंट को भी दोनों पक्षों ने स्वीकार किया।

भारतीय मूल के लोग दोनों देशों को जोड़ने वाले सेतु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके स्वागत में यहां 800 से अधिक नर्तकों ने लय और ताल के साथ रिकॉर्ड सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उनकी साल 2026 की पहली विदेश यात्रा है। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय समुदाय के बीच आकर बेहद खुश हैं। भारत और मलेशिया के लोगों के दिलों को जोड़ने वाली बहुत सी बातें हैं। दोनों देशों की समानता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मलेशिया की रोटी कनाई और भारत का मालाबार परोटा एक जैसे हैं। नारियल, मसाले और यहां की तेह तारिक का स्वाद कुआलालंपुर और कोच्चि, दोनों जगह एक जैसा ही महसूस होता है। दोनों देशों के लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि भारतीय भाषाओं और मलय भाषा में कई शब्द एक जैसे हैं। भारतीय फिल्में और संगीत मलेशिया में बहुत लोकप्रिय हैं।

मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने सदियों से अपनी परंपराओं को बनाए रखा है। 'मन की बात' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पूरे भारत को बताया था कि मलेशिया के 500 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को भारतीय भाषाएं सिखाई जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तमिल दुनिया के लिए भारत का उपहार है। तमिल साहित्य शाश्वत है, तमिल संस्कृति वैश्विक है। तमिल लोगों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से मानवता की सेवा की है।

मलेशिया में 100 से अधिक भारतीय आईटी कंपनियां काम कर रही हैं जिससे हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। मलेशिया-भारत डिजिटल काउंसिल डिजिटल सहयोग के लिए नए रास्ते खोल रही है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत का यूपीआई सिस्टम जल्द ही मलेशिया में शुरू होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने प्रवासी भाई-बहनों का हमेशा खुली बाहों से स्वागत करेगा। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय पर जोर देते हुए कहा कि अब छठी पीढ़ी तक के भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड के पात्र होंगे। जल्द ही मलेशिया में भारत का एक नया दूतावास खोला जाएगा, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे।

भारत-मलेशिया के महत्वपूर्ण समझौते...

- ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण।
- भ्रष्टाचार से निपटना और रोकना।
- संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा।
- आपदा प्रबंधन।
- सेमीकंडक्टर क्षेत्र।
- अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस।
- व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
- भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मलेशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद।
- स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग।

पीएम मोदी की व्यापार प्रमुखों के साथ बैठक

मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने चार प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मलेशियाई व्यवसायियों को विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्योग जगत के प्रमुखों ने भारत सरकार द्वारा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में किए गए सुधारों की प्रशंसा की और भारत की विकास गाथा में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया।

पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों असली ताकत पीपल टू पीपल संबंध है। भारतीय मूल के लगभग तीस लाख मलेशियाई नागरिक दोनों देशों के बीच लिविंग ब्रिज है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत और मलेशिया, जो समुद्री पड़ोसी हैं, उनकों आपसी संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। ■

आर्थिक शक्ति का संगम

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से खुले नए अवसर

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सक्रिय और आत्मविश्वासी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी क्रम में भारत-अमेरिका व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर उभरा है। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक शक्तियों के बीच हुआ यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला को नई दिशा देने के साथ-साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी करेगा सशक्त...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में अमेरिकी यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच एक संतुलित और पारस्परिक रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नियमति रूप से चर्चा हो रही थी। पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर गहन वार्ता हुई जिसके बाद अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते की ओर बढ़े। इसी का परिणाम है कि दो फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। भारतीय वस्तुओं पर जो टैरिफ तय किया गया है वह अमेरिका द्वारा दूसरे कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से बहुत कम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझोते की रूपरेखा पर हुई सहमति का स्वागत किया। यह

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत का संयुक्त वक्तव्य

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यह अंतरिम व्यापार समझौता पारस्परिक हितों और ठोस परिणामों पर आधारित है। साथ ही यह संतुलित व्यापार के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका-भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की प्रमुख शर्तें...

- भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों और अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा। इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं।
- यूएसए 2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश में संशोधन करेगा, इसके तहत भारत में निर्मित वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा, जिसमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी शामिल हैं।
- अमेरिका, भारत के कुछ विमानों और विमान पुर्जों पर लगाए गए टैरिफ को हटा देगा।
- अमेरिका और भारत ऐसे निर्माण नियम बनाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि समझौते के लाभ मुख्य रूप से दोनों देशों को ही प्राप्त हों।
- अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान करेंगे।
- लागू तकनीकी विनियमों के अनुपालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों के लिए अपने-अपने मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे।
- निर्धारित टैरिफ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हैं कि दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताओं में परिवर्तन कर सकता है।
- अमेरिका इस बात की पुष्टि करता है कि वह बीटीए की वार्ता के दौरान भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ कम करने के भारत के अनुरोध को ध्यान में रखेगा।
- अमेरिका-भारत आर्थिक सुरक्षा की रूपरेखा को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं ताकि आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और नवाचार को बढ़ाया जा सके। इसके लिए तीसरे पक्ष की गैर-बाजार नीतियों से निपटने के लिए पूरक कार्रवाई की जाएगी।
- भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, बहुमूल्य धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदेगा।

समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती प्रगाढ़ता, विश्वास और गतिशीलता का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' की परिकल्पना को मजबूत करेगा। साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगा। निवेश और प्रौद्योगिकी

भारत-यूएसए व्यापार समझौते के मुख्य बिन्दु

30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार में भारत को प्राथमिकता वाले साझेदारों के रूप में पहुंच मिली।

- वस्त्र एवं परिधान पर शुल्क 50% से घटकर 18% तक हुआ, रेशम को 113 बिलियन डॉलर के अमरीकी बाजार में 0% आयात शुल्क पर पहुंच।
- मशीनों पर टैरिफ घटाकर 18% किया गया, जिससे 477 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार में अवसर खुले।
- 1.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय कृषि निर्यात को अमेरिका में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
- मसाले, चाय, कॉफी, फल, मेवे और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे प्रमुख उत्पादों को शून्य शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया है।
- डेयरी, मांस, पोल्ट्री और अनाज जैसे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।

“

प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अब भारत में बने उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है। पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रतिस्पर्धी देशों पर अमेरिकी टैरिफ

भारत-यूएसए अंतरिम व्यापार समझौते में दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ लगाया गया है। कई प्रतिस्पर्धी निर्यातक देश अमेरिकी बाजार में अभी भी ज्यादा शुल्क का सामना कर रहे हैं, जिनमें चीन (35%), वियतनाम (20%), बांग्लादेश (20%), मलेशिया (19%), इंडोनेशिया (19%), फिलीपींस (19%), कंबोडिया (19%) और थाईलैंड (19%) शामिल हैं।

इन भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका में टैरिफ हुई कम

चमड़ा एवं जूते, रत्न एवं आभूषण, गृह सज्जा, खिलौने, मशीनरी और पुर्जे (विमान के पुर्जों को छोड़कर)।

कृषि एक्सपोर्ट के लिए जीरो ड्यूटी एक्सेस

अमेरिका 1.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। जिन उत्पादों को फायदा होगा उनमें मसाले, चाय और कॉफी और उनके अर्क, खोपरा और नारियल का तेल, वनस्पति मोम, सुपारी, ब्राजील नट्स, काजू और शाहबलूत जैसे मेवे, एवोकाडो, केले, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, शिटाके और मशरूम सहित फल और सब्जियां, जौ और कैनरी बीज जैसे अनाज, बेकरी उत्पाद, कोको, और कोको से बने उत्पाद, तिल और खसखस, फल का गूदा, जूस और जैम जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत का इन देशों के साथ हुआ व्यापार समझौता

यूरोपीय संघ के साथ-साथ भारत सरकार ने 2014 से मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की है। 2025 में भारत ने ओमान और यूके के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।

साझेदारी प्रगाढ़ होगी, सुगम और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत मिलेगी और वैश्विक विकास में भी योगदान देगी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से श्रम प्रधान और विनिर्माण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। समझौते में खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। साथ ही, लघु और मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाजा वैकल्पिक बाजार और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना जरूरी है। वाणिज्य मंत्री ने संसद में स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे। ▪

Narendra Modi @narendramodi

यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि India AI Impact Summit के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है।

दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये।

विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा॥

Rajnath Singh @rajnathsingh

राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ, केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा नहीं है। एक राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा, एक राष्ट्र की सभ्यतागत चेतना की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे संत सदियों से भारत की सांस्कृतिक धारा के संरक्षक हैं।

Amit Shah @AmitShah

जो PM गरीब कल्याण अन्न योजना देश के गरीबों के कल्याण का माध्यम बनी है, वह टेक्नोलॉजी से संपन्न होकर और भी अधिक पारदर्शी बनने जा रही है। गांधीनगर (गुजरात) में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया। इससे देश भर में PDS आधुनिक व सरल बनेगा और मोदी जी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के संकल्प को जमीन पर उतारेगा।

साथ ही पोषण, अन्नपूर्ति मशीन व उपभोक्ता हित से जुड़ी अन्य 5 योजनाओं का लोकार्पण किया व 'गरिमा पोषण' कार्यक्रम की राशि वितरित की।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना' की पहल का ऐतिहासिक निर्णय #ViksitBharatBudget में लिया गया है। इस योजना के जरिए खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, बुनकरों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

#UnionBudget2026

Sarbananda Sonowal @sarbana...

Gratitude to Hon'ble PM Shri @narendramodi ji for inspiring thousands of grassroots BJP karyakartas at the Booth Vijay Sankalp Sabha in Guwahati.

PM Modi ji gave the mantra of reaching every doorstep to take the message of development to all. Under his leadership, we are set for a rousing third term in Assam.

#PMModiInAssam

Gajendra Singh Shekhawat @gs...

किसान पहले, देश सर्वोपरि! 🌾🇮🇳

मोदी सरकार की स्पष्ट नीति — किसान हित से कोई समझौता नहीं।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील में साफ संदेश: रागी, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, सांवा, कंगनी, ओट्स, अमरनाथ और नारियल जैसे भारतीय अनाज बाहर से नहीं आएंगे।

आत्मनिर्भर कृषि, स्वदेशी अन्न और अन्नदाता का सम्मान — यही है नए भारत की असली पहचान। 💪🌾

आज भारत में राजनीतिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था भी बेहतर, इसीलिए ट्रेड डील्स में हम मजबूत स्थिति से बात कर रहे: मोदी

मोदी बोले- यह बजट 2026 नहीं, आगे 25 साल के लिए रफ्तार देता है...

इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 389 किलोमीटर बढ़ेगा

कैबिनेट ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों में अतिरिक्त पटरियां बिछाने की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी

परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 18,509 करोड़ रुपये है और ये वर्ष 2030-31 तक पूरी होंगी

PM का विमान पूर्वोत्तर के पहले इमरजेंसी लैंडिंग स्थल पर उतरा

प्रधानमंत्री मोदी ने मोरान के ईएलएफ का किया उद्घाटन

5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन

सेवा तीर्थ: पहले दिन कई बड़े फैसले

अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी, घायलों को मिलेगा 1.5 लाख का कैशलेस इलाज

10,000

दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा भारत: मोदी

नई वैश्विक व्यवस्था को नेतृत्व और आकार दे रहा भारत: PM

फंड ऑफ फंड्स-2.0

स्टार्टअप को पूंजी सहायता के लिए 10,000 करोड़ का कोष

स्टार्टअप, शहरी विकास व रेलवे से जुड़ी 1.60 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर

डीप टेक, प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण और शुरुआती चरण के स्टार्टअप को मिलेगी मदद, नए रोजगार पैदा होंगे

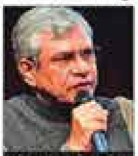

एक लाख करोड़ के कोष से शहरों का कायाकल्प

दिल्ली-अंबाला के बीच तीसरी व चौथी रेल लाइन बनेगी

आज से 5 दिन तक दुनिया की 'डाटा कैपिटल' बनेगी दिल्ली

सबसे बड़ी एआई समिट: 100+ सीईओ, 20+ राष्ट्राध्यक्ष और 135+ देशों के डेलीगेट्स जुटेंगे

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च

सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की थीम – सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी पहले से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से जुड़े लोगों से भारतीय उत्पाद को भरोसेमंद बनाने की बात कह रहे हैं। साथ में, केंद्र सरकार उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देने और भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती सहित उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए चला रही हैं कई डिजिटल प्लेटफॉर्म...

- उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए पुराने कानून को रद्द कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू।
- 1 जनवरी, 2025 से **https://e-jagriti.gov.in/** पोर्टल लॉन्च। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फेसलेस ऑनबोर्डिंग जैसी सुविधा से उपभोक्ता शिकायत निवारण को बेहतर बनाता है।
- मुकदमेबाजी से पूर्व शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर 1915 पर करें शिकायत। शिकायत निवारण की समय सीमा 45 दिन। बीते तीन वर्ष से औसतन मासिक 1 लाख से अधिक शिकायतें यहां आती हैं।

"विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपभोक्ताओं का अभिनंदन, जिनकी क्रय शक्ति पर हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति निर्भर है। भारत सरकार न केवल उपभोक्ता संरक्षण, बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 मार्च, 2026
आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 19 फरवरी 2026, कुल पृष्ठ-60)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित